राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 36 अंक 9 दिसम्बर 2015 मूल्य 5 रु. पृष्ठ 40

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ज्ञान • शील • एकता

61

राष्ट्रीय अधिवेशन

उद्घाटन

युवा पुरस्कार

समापन

7-8 नवंबर को 'नयी शिक्षा नीति' पर कोलकाता में हुए संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए पूर्व यूजीसी अध्यक्ष डा. अरूण निगवेकर तथा AICTE के अध्यक्ष डा. अनिल सहस्रबुद्धे

उद्घाटन सत्र में मंच पर पूर्व यूजीसी अध्यक्ष डा. अरूण निगवेकर तथा AICTE के अध्यक्ष डा. अनिल सहस्रबुद्धे, अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे तथा अन्य मान्यवर

संगोष्ठी में उपस्थित पश्चिम बंग के राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलपति स्वामी आत्मप्रियानंद तथा सुपर्णो मोइत्रा

समापन सत्र में मंच पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, NAAC के निदेशक डा. डी. पी. सिंह, AICTE के अध्यक्ष डा. अनिल सहस्रबुद्धे तथा अन्य

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक मण्डल

आशुतोष

संजीव कुमार सिन्हा

अवनीश सिंह

अभिषेक रंजन

फोन : 011-23216298

ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com

ब्लॉग :chhatrashaktiabvp.com

वेबसाईट :www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली - 110007 से प्रकाशित एवं 102, एल. एस. सी., ऋषभ विहार मार्केट दिल्ली-92 से मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय

''छात्रशक्ति भवन''

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली - 110002

अनुक्रमणिका

विषय	पृ. सं.
सम्पादकीय	4
देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका अहम –प्रो. देबरॉय	5
असहिष्णुता देश में नहीं, तथाकथित बुद्धिजीवियों के दिमाग में है	7
काशी विद्यापीठ छात्र संघ अध्यक्ष पद पर अभाविप का कब्जा	8
भावनात्मक एकता बढ़ाता अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन – आकाश कुमार राय	9
सोच बदलने से मिलेगा बेटियों को सम्मान	11
डा. नागेश ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष और विनय बिदरे राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित	12
अभाविप के विदर्भ कार्यालय का उद्घाटन	13
अभाविप के प्रदूषण मुक्त नर्मदा अभियान का दिखा असर	14
पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा हम सभी का	15
61वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव	16
झलकियां 61 वें राष्ट्रीय अधिवेशन की	19–22
साक्षात्कार	26
शिक्षा पर संवेदनहीन बुद्धिजीवी – अवनीश राजपूत	29
विद्यार्थी परिषद की इमारत की नींव थे अरुण भाई यार्दी	31
गर्व से कहो मैं हिन्दुस्तान की बेटी हूँ – प्रो चावला	32
मधेशी आन्दोलन और नेपाल में राजनीतिक हलचल का सच	33
बौद्धिक सैनिक की तरह कार्य करते है, परिषद के कार्यकर्ता	35
देश में काम करने को प्रतिबद्ध युवा	36
सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय में अभाविप की तीन सीटों पर जीत	37
राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

हाल ही में छद्म धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों द्वारा केन्द्र की सरकार के विरुद्ध "असहिष्णुता को लेकर जो बहस चलायी गयी, वह प्रकारान्तर से भारत के बहुसंख्यक समाज के मूल्यों और मर्यादाओं पर चोट थी। वन्देमातरम् और योग के विरोध के पश्चात् यह बहस अखलाक की हत्या तक पहुँची। असहिष्णुता का यह आंदोलन उन मूल्यों के खिलाफ था जो भारत की पहचान है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को विश्वभर में जितना समर्थन और सराहना मिली, उसे इन कथित बुद्धिजीवियों ने भारत के गौरव के रूप में स्वीकार करने के स्थान पर मोदी को मिलती स्वीकार्यता के रूप में देखा और उसके विरोध पर उतर आये।

जिन लोगों ने सरकारी पुरस्कारों को लौटाने की घोषणा की, उनमें से ज्यादातर ने अलंकरण लौटाये न कि पुरस्कार राशि। चैनल के कार्यक्रम में पुरस्कार लौटाने का तमाशा भी देश ने देखा। इसका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना था, तो वे इसमें असफल रहे। यदि यह प्रचार पाने का सस्ता नुस्खा था तो उन्हें कुछ मात्रा में सफल कहा जा सकता है। लेकिन यह सफलता भी तब बेमानी लगेगी जब वे एकान्त में बैठकर इसके परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। जिस तरह से भारत के मान बिन्दुओं और पहचान पर हमला करने की कोशिश हुई उसने देश में एक बहस खड़ी की। किन्तु यह उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी जिधर यह बुद्धिजीवी उसे ले जाना चाहते थे। इसके विपरीत वह अपनी पहचान की तलाश की ओर बढ़ चली।

भुवनेश्वर में सम्पन्न अभाविप का **61**वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बहस की छाया में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में प्रायः वक्तव्यों और व्याख्यानों में इसका संदर्भ जुड़ना स्वाभाविक था। एक प्रस्ताव भी इस घटनाक्रम पर पारित किया गया। अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता प्रो. विवेक देबरॉय सहित सभी वक्ताओं ने भारत की वैश्विक पहचान और उसके मूल्यों पर बल दिया।

तात्कालिक बहस से परे भारत की जीवन दृष्टि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की है। पर्यावरण से जुड़े विषय पर भी श्री इम्तियाज अली को पुरस्कार प्रदान करते समय भारतीय दृष्टि का विषय एक बार फिर उठना ही था। यही स्थिति प्रस्ताव पारित करते हुए भी बनी।

भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज 'सहिष्णुता' का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस 'सहिष्णुता' का अर्थ कायरता नहीं है। इसलिये बुद्धिजीवी गिरोह द्वारा सहज-सरल भारतीय मानस पर किया जाने वाला यह बौद्धिक आक्रमण भी काल के प्रवाह पर बिना कोई रेखा छोड़े विलीन हो जाने वाला है। हमारी सहिष्णुता ने गत सैकड़ों वर्षों में ऐसे अनेक 'असहिष्णु' अभियान झेले हैं और अपनी 'सहिष्णुता' के बल पर ही जीत हासिल की है।

शिक्षा के क्षेत्र में असहिष्णुता के उदाहरण देखने हों तो अभाविप का हैदराबाद कार्यालय इसका आदर्श स्थान है जहां दीवारों पर लगे बलिदानी कार्यकर्ताओं के चित्र इन्हीं 'असहिष्णुता' के झंडाबरदारों के खूनी खेलों का इतिहास बताते हैं।

1980 में गणतंत्र दिवस पर कुलपति और शिक्षकों की उपस्थिति में तिरंगा जलाने की कोशिश कर रहे वामपंथी कार्यकर्ताओं का विरोध करने वाले जगनमोहन रेड्डी को बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। एक-एक कर दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को खोने के बाद भी अभाविप सीना ताने खड़ी रही। राष्ट्रीय विचारों के पक्ष में जान हथेली पर रख कर आतंकियों की बंदूकों के सामने सीना ताने खड़े रहना अगर 'असहिष्णुता' है तो परिषद् इसकी दोषी है। लेकिन उस बंदूक के पीछे किसका कंधा है और उस कंधे के पीछे किसका दिमाग है, यह देखना होगा।

हिंसा को बौद्धिक संरक्षण देना भी हिंसा का ही एक स्वरूप है। इस बौद्धिक हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रवादी चिंतन धारा का एक-एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। जो आज असहिष्णुता का राग अलाप रहे हैं वे बहुसंख्यक समाज की संवेदना पर चोट करने के लिये किये जाने वाले बीफ फेस्टीवल पर चुप्पी ही नहीं साधते बल्कि उनके समर्थन में खड़े होने की बेशर्मी भी दिखाते हैं। अगर बहस खड़ी हो ही गयी है तो उसे निर्णायक निष्कर्ष तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय अधिवेशन के विस्तृत विवरण को संजोये यह अंक आपके सम्मुख है। अगला अंक 'युवा भारत -समर्थ भारत' विशेषांक है जो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोकार्पित होगा। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।

अधिवेशन उद्घाटन

देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका अहम -प्रो. देबरॉय

भुवनेश्वर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नगर स्थित एसओए विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। अधिवेशन के निमित्त पहुँचे अतिथियों का स्वागत करते हुए आईआईटी खड़गपुर के पूर्व निदेशक प्रो. दामोदर आचार्य ने कहा कि अभाविप के माध्यम से शिक्षा को लेकर एक नयी सोच विकसित हुई है। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर उन्होंने लगाम लगाये जाने की बात कही। साथ ही उत्कल शिरोमणि पंडित गोपबंधु दास को याद करते हुए उनके बताये मार्ग पर चलने की बात कही।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पद्मश्री प्रो. विवेक देबरॉय ने किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज हम भारतीय होने पर गौरव का अनुभव करते हैं परन्तु जब हम विद्यार्थी थे तो पिछली सरकारों ने गर्वबोध की इच्छा होने के बावजूद गौरव महसूस करने का अवसर नहीं दिया क्योंकि सरकार स्वयं देश के प्रति स्वाभिमानशून्य थी। युवाओं का आह्वान करते हुए प्रो. देबरॉय ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने और समृद्ध बनाने का दायित्व केवल शासन का नहीं है अपितु आप सभी युवाओं की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज के युवा देश के भविष्य ही नहीं बल्कि भविष्य का देश भी इनका है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लेखक श्री अमीश त्रिपाठी ने देशभर से आये प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए गौरव का अनुभव हो रह है कि मेरे व्यक्तित्व निर्माण में मेरे

परिवार की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही। मेरे आगे बढ़ने में परिवार हमेशा सहयोगी रहा है। यदि परिवार साथ है तो कुछ भी असम्भव नहीं। अतः युवा पीढ़ी से यह अपेक्षा है कि आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों, अपने परिवार, अपनी संस्कृति को वे ना भूलें। अपने सपनों को हृदय में जीवित रखें और समय आने पर उन्हें साकार रूप दें।

महामना मदन मोहन मालवीय को याद करते हुए श्री त्रिपाठी ने उनके व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि आज उनके परिवार पर सरस्वती जी की जो भी कृपा है वह मालवीय जी की ही देन है। श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि आज के युवा को राम के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। देशहित एवं न्याय की रक्षा हेतु तत्पर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं परन्तु उससे ना घबराते हुए सदैव राष्ट्रहित एवं जनहित का ध्यान रखना चाहिए। यह भगवान बुद्ध एवं महात्मा गांधी के जीवन से भी सीख सकते हैं।

इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर ने कहा कि 1971 के बाद से बांग्लादेश के सारे पोर्ट बंद थे और उत्तर पूर्व के राज्यों तक आवश्यक सामानों की आपूर्ति में बाधा पहुँचती थी। मगर वर्तमान सरकार के सद्प्रयासों से आज बांग्लादेश के सारे पोर्ट भारत के लिए खुल गये हैं। जिससे पूर्वोत्तर राज्यों को निश्चित ही लाभ मिला है। पहले व्यापार के लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए हफ्तों का समय लगता था मगर बांग्लादेश के पोर्ट व्यापार के लिए खुलने के बाद समय की भी बचत हो रही है।

वहीं, असहिष्णुता के मुद्दे पर बोलते हुए श्री बोरिकर ने कहा कि 1984 के दंगों, सिंगूर–नंदीग्राम में हुई हत्या–बलात्कार की घटनाओं एवं अन्य इस प्रकार के हिंसक कृत्यों पर तो देश के लेखक एवं बुद्धिजीवियों ने कभी कुछ नहीं कहा। फिर आज असमय ही ऐसी कौन सी घटना ने उन्हें उद्वेलित कर दिया कि वो इस प्रकार रुदन कर रहे हैं। वामपंथी राजनीति से प्रेरित कलाकारों एवं लेखकों को समझना होगा कि उन्होंने देश की जनता का अपमान किया है, जिसने उन्हें सम्मान प्रदान किया।

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नागेश ठाकुर ने कहा कि हमारा देश एक ऊर्जावान देश है। इस ऊर्जा का सही एवं सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि परिषद् की जागरुकता समाज के छोटे–छोटे विषयों से लेकर राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय विषयों तक है। इस सन्दर्भ में उन्होंने जल–जंगल–जमीन व जानवर की रक्षा का संकल्प भी दोहराया।

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का दिसम्बर 2015 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों तथा खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई–मेल पर अवश्य भेजें।

"छात्रशक्ति भवन,"
26, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली – 110002
फोन : 011–23216298
ई–मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाईट : www.abvp.org

'असहिष्णुता देश में नहीं, तथाकथित बुद्धिजीवियों के दिमाग में है'

भारतीय संस्कृति का आधार है 'वसुधैव कुटुम्बकम्' : सुनील आंबेकर

देश की संस्कृति से जुड़कर समाज के समग्र विकास के लिए कार्य करने की भावना के साथ युवाओं के चरित्र निर्माण में सहायक होने वाला छात्रों–युवाओं का संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्। अभाविप की स्थापना ही छात्र हितों को ध्यान में रखकर युवाओं के पथ प्रदर्शक के तौर पर हुई है, जिसमें वह अपनी महती भूमिका अदा कर रही है। अभाविप सामाजिक परिदृश्य में रचनात्मक क्रियाशील और विकासोन्मुखी विचारों का द्योतक है। अपने सुनियोजित विचार के बलबूते ही परिषद् देश की परिस्थितिजन्य समस्याओं के समाधान हेतु सदैव तत्पर रहती है। उक्त बातें अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने परिषद् के 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अभाविप की वैचारिक भूमिका विषय पर अपना कथन रखते हुए कहीं।

श्री आंबेकर ने कहा कि देश यह सोचता है कि क्या कोई विद्यार्थी संगठन समाज में गम्भीर भूमिका का निर्वाह कर सकता है? इनका देश की परिस्थिति से कोई सरोकार है क्या? छात्र संगठन देश की परिस्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं? अभाविप की अब तक की यात्रा ने इन आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए यह सिद्ध किया कि अभाविप ने समाज में अपनी भूमिका का गम्भीरता से निर्वाह करते हुए देश की समस्याओं पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने का कार्य किया है। श्री आम्बेकर ने परिषद् के विचार को भारत का विचार बताते हुए इसे छात्रों के बीच व्यापक रूप से ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कहा कि कुछ तथाकथित बुद्धजीवी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में धर्म से निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता। धर्म के साथ चलने पर समाज एवं राष्ट्र को ध्येय मानकर व्यक्ति कार्य करता है। उन्होंने कहा कि हमारा विचार दूसरों को नष्ट करने अथवा शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करने का नहीं अपितु 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' है। इसके लिए हमें स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है क्योंकि व्यक्ति को स्वयं की पहचान हो तो वह स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है, ऐसे में सभी को अपने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की पहचान कर उससे जुड़ना होगा।

श्री आंबेकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार की चर्चा करते हुए कहा कि 21वीं सदी में जिस प्रकार की देशभक्ति की आवश्यकता है संघ ने वैसा ही विचार समाज को दिया है। छात्रों से देशवासियों की सेवा के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि सबको सम्मान, सुरक्षा एवं अवसर मिले इस हेतु समस्त समाज के निर्माण में छात्र शक्ति को अपनी महती भूमिका का निर्वाह करना होगा।

श्री आंबेकर ने वर्तमान परिदृश्य को लेकर कहा कि भारत की वर्तमान व्यवस्था भारतीय आत्मा के अनुरूप नहीं है, अतः व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। परिषद् की गतिविधियों को भारत का गौरव बढ़ाने वाला बताते हुए श्री आंबेकर ने कहा कि चारित्र्य सम्पन्न व्यक्ति के निर्माण से ही समाज और राष्ट्र का

निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि हम सब भारत माता के पुत्र हैं और इसी भाव से देश की सेवा में लगे हुए हैं। भारत की एकात्मता का मूल आधार संस्कृति है। इसी के तहत समरस समाज का निर्माण, महिला सुरक्षा, देश की सुरक्षा, शिक्षा का भारतीयकरण के साथ देश को समर्थ, और शक्ति सम्पन्न बनाना हमारा लक्ष्य है।

राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने कहा कि परिषद् ने छात्रों को सकारात्मक शक्ति के रूप में माना है और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में समाज में स्थापित करने का कार्य किया। विद्यार्थी परिषद् के दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए श्री सुनील आंबेकर ने कहा कि परिषद् छात्रों को संकीर्ण नहीं अपितु व्यापक अर्थात् अखिल भारतीय दृष्टिकोण प्रदान कर उसे रचनात्मक कार्य में प्रवृत करता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान को दुनिया के लिए वरदान बताते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक अवधारणा दूसरों के साथ संघर्ष की नहीं अपितु 'वसुधैव कुटुम्बकम' की है।

काशी विद्यापीठ छात्र संघ अध्यक्ष पद पर अभाविप का कब्जा

पहली महिला अध्यक्ष बनीं आयुषी श्रीमाली

वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्रसंघ के अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आयुषी श्रीमली ने जीत हासिल की है। आयुषी श्रीमाली ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाते हुए विश्वविद्यालय में नया इतिहास रच दिया। काशी विद्यापीठ में पहली बार कोई महिला उम्मीदवार छात्रसंघ अध्यक्ष चुनी गई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी छात्र एकता मंच के शशांक सिंह रघुवंशी को 172 मतों से पराजित किया। आयुषी को कुल 1261 मत मिले। कुलपति पृथ्वीश नाग ने नव–निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलायी।

चुनाव जीतने के बाद छात्रशक्ति से बातचीत करते हुए आयुशी श्रीमली ने इस जीत का श्रेय अभाविप कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं को दिया। आयुशी की माने तो अभाविप ही ऐसा छात्र संगठन है जो वर्षभर अपने रचनात्मक व संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए छात्रों की समस्या को उठाता है इसीलिए विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमपर भरोशा जताया है और हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकताओं में छात्र हितों की रक्षा और शिक्षा से जुड़े सभी काम सर्वोपरि हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश, परीक्षा और परिणाम को समय पर कराना है। इसके अलावा परिसर में रचनात्मक कार्यों के जरिए शिक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन के प्रति जागरुक करना भी उनकी प्राथमिकता में है।

भावनात्मक एकता बढ़ाता अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन

✍ आकाश कुमार राय

हमारा पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक संपदा एवं सांस्कृतिक वैभव का असीम भण्डार है जो कि सम्पूर्ण भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी अन्यत्र दुर्लभ है। यहां के विभिन्न समुदायों की अनेक भाषाएं और उनकी परम्पराएं एक ऐसे बहुरंगी समाज की रचना करती हैं, जिसे देखकर कोई भी सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। यही कारण है कि इसे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लोग भारतीय संस्कृति का मुख्य द्वार कहते हैं। इस छोटे से क्षेत्र में 220 से अधिक जातीय समूहों के लोग निवास करते हैं। इनकी जितनी जातियां हैं उतनी ही भाषाएं है, बावजूद इसके सभी एक संस्कृति से जुड़े हैं। इसीलिए भारत को विविधता में एकता वाला देश कहते हैं।

विविधता में एकता के मूल मंत्र को 1966 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने देश के दूर–दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'अन्तर राज्य छात्र जीवन दर्शन' के नाम से एक अभिनव प्रकल्प प्रारम्भ किया। जागरूकता, एकात्मता एवं स्वावलम्बन के तीन सूत्रीय लक्ष्य को लेकर पूरे देश में सील (SEIL) नाम से काम कर रहा यह प्रकल्प आज अपनी स्थापना की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है। सुदूर क्षेत्रों के लोगों का शेष भारत से परस्पर संवाद स्थापित करने के साथ ही जीवन की विविधताओं में निहित भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को निरूपित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

इसके साथ ही इन क्षेत्रों के युवाओं को विभिन्न स्तर पर अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे अपने देश की विविधता में एकता का अनुभव कर सकें। इस क्रम में अभाविप अपने इस प्रकल्प के माध्यम से समय–समय पर अपनी रचनात्मक और संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित कर रही है जो काफी प्रभावी रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 'सील' ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम कर रही सभी राष्ट्रवादी ताकतों के लिए मंच एवं नेतृत्व प्रदान किया है। इतना ही नहीं इस प्रकल्प के माध्यम से अब तक पच्चीस से अधिक एकात्मता यात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों प्रतिभागियों और देश के अन्य स्थानों पर निवास करने वाले इनके यजमान परिवारों का ध्यान पूर्वोत्तर की ओर आकृष्ट कराया गया। सुनियोजित यात्राओं के बीच होने वाला विचारों का यह मंथन जीवन भर के संबंधों में परिवर्तित हुआ और अगली पीढ़ी तक विस्तारित हो रहा है।

पिछले पच्चीस वर्षों की अपनी यात्रा के माध्यम से सील द्वारा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों और जरूरतों के प्रति ईमानदार और संवेदनशील रहते हुए स्थायी समाधान खोजने का सफल प्रयोग किया गया है। पूर्वोत्तर प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर सील द्वारा कराये गये विविध अध्ययन दलों के सर्वेक्षण संगठन की सोच को अधिक गहरा बनाने में लाभदायक सिद्ध हुए हैं।

सील द्वारा पूर्वोत्तर के छात्रों को शेष भारत की भाषा, खानपान, वेशभूषा, त्यौहार, पूजा–पद्धति इत्यादि का अवलोकन करते हेतु विशेष भ्रमण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, ताकि वो अन्य राज्यों को भी समझ सकें। इसके पश्चात् छात्र अपने अनुभव के आधार पर 'हम सब एक हैं' यह विश्वास लेकर अपने प्रांत में जाते हैं और राष्ट्रीय एकात्मता का आधारस्तम्भ बनते हैं।

'अन्तर राज्य छात्र जीवन दर्शन' के तहत राष्ट्रीय एकात्मता के प्रयासों को बढ़ावा देने एवं सांस्कृतिक सौहार्द की भावना को प्रबल करने के साथ सुदूर क्षेत्रों में परस्पर संवाद के द्वारा सभी प्रकार के भेद व विषमताओं को मिटाने वाली राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 'भारत को जानो' का आयोजन इस वर्ष दो जनवरी, 2015 से 24 जनवरी, 2015 तक किया गया। इस यात्रा में पूर्वोत्तर के छह राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय) के कु 30 जिलों से 21 जनजातियों के 66 छात्र–छात्राओं (24 छात्राएं, 37 छात्र एवं 5 संयोजक) ने भारत के 11 राज्यों के 11 शहरों (बनारस, शिमला, जम्मू, दिल्ली, झांसी, ब्रह्मपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई) में निवास व भ्रमण किया।

इस क्रम में दिल्ली में आयोजित हुए पूर्वोत्तर छात्र–युवा नेता संसद का केन्द्रीय विषय 'पूर्वोत्तर के विकास में युवा नेताओं की भूमिका' रही। जिसमें पूर्वोत्तर के कुल छह प्रान्तों से 52 छात्र संगठनों के 130 छात्रनेता उपस्थित रहे। संसद में पर्यटन तथा आधारभूत संरचना के विकास हेतु योगदान, पूर्वोत्तर के विकास हेतु शान्तिपूर्ण वातावरण का निर्माण कैसे हो एवं सामूहिक प्रयास जैसे विषयों पर गहनता से चर्चा हुई। जिसके बाद सभी संगठनों ने मिलकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कार्य करने, शिक्षा–स्वास्थ्य के विकास को प्राथमिकताओं में लाने, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु सामूहित प्रयास, नशामुक्त–भ्रष्टाचारमुक्त–आतंकवादमुक्त पूर्वोत्तर, युवा शक्ति का विकास तथा शेष भारत में पढ़ रहे पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए भयमुक्त माहौल का निर्माण करना जैसे विषयों पर सहमति बनी। इन सभी विषयों पर एकजुट प्रयास करने को लेकर हुआ निर्णय ही इस संसद की सफलता रही। ■

सोच बदलने से मिलेगा बेटियों को सम्मान

अभाविप के प्रांत छात्रा सम्मेलन में हुई महिला सम्मान के मुद्दे पर चर्चा

रेवाड़ी। अपने अन्दर छिपी नारी शक्ति को जगाने से ही बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। वंशवाद की बात आती है तो बेटियों का नाम सबसे आगे आता है। छोटी मानसिकता की सोच बदलने से ही बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। ये बातें हरियाणा की महिला एवं समाज कल्याण मंत्री कविता जैन ने अभाविप द्वारा आयोजित प्रांत छात्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहीं। सम्मेलन में प्रदेशभर से 21 जिलों के विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं ने हिस्सा लिया।

श्रीमती कविता जैन ने कहा कि जब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं आयेगा तब तक कोई भी सरकार लड़कियों पर होने वाले अत्याचार पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा पायेगी। इसके लिए आम नागरिक को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। जिस समाज में बेटियों का सम्मान नहीं होगा वह राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की थी। बेटियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए माता–पिता और समाज के लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है।

कविता जैन ने कहा कि बेटी को सम्मान और स्वावलम्बन दिलाना है तो समाज और परिवार को आगे आना होगा। कानून और सरकार तो गलत काम करने वालों को दण्ड दिला सकता है। बेटी की शिक्षा का प्रबंध करना सरकार का काम है, बेटी को शिक्षा के लिए घर से बाहर निकालने का काम परिवार और समाज का है। इसलिए समाज की सोच को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि कल्पना चावला, सायना नेहवाल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज आदि महिलाओं ने अपने दम पर समाज में अलग पहचान बनाई।

समाजसेवी एवं उद्योगपति रवि गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम सत्र के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ टंकेश्वर कुमार ने कहा कि वे पिछले 20 साल से अभाविप की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए हैं। वे शिक्षा से जुड़े हैं और शिक्षा तक ही सीमित रहेंगे। उन्होंने नारी शक्ति को सशक्त होने के लिए आत्मशक्ति को जागरूक करने पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सभी समस्याएं समाप्त हो जायेंगी।

मुख्य वक्ता के रूप में अभाविप छात्रा प्रमुख ममता यादव ने परिषद् के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए संगठन के नारे– शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और स्वावलम्बन की व्यवहारिकता पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई, 1949 को पंजीकृत हुआ छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) अपने उतार–चढ़ाव और संघर्ष की यात्रा तय करते हुए प्रत्येक छात्र में 'शिक्षा जीवन के लिए–जीवन वतन के लिए' की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। विद्यार्थी परिषद् का प्रयास है कि लोक शिक्षा, लोक सेवा एवं लोक संघर्ष द्वारा विद्यार्थी समुदाय परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। यह संगठन भूकम्प, सुनामी या बाढ़ जैसी नैसर्गिक आपदाओं में बढ़–चढ़कर सहयोग, रक्तदान, पौधारोपण जैसी पर्यावरण तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर अपना सामाजिक दायित्व निभा रहा है। ■

डॉ. नागेश ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष और विनय बिदरे राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित

डॉ. नागेश ठाकुर (शिमला) और श्री विनय बिदरे (बंगलुरू) देश के अग्रणी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के क्रमशः राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री के पद के लिए सत्र 2015–16 हेतु निर्वाचित हुये हैं। यह घोषणा अभाविप केन्द्र कार्यालय (मुंबई) द्वारा की गयी। अभाविप केन्द्र कार्यालय से चुनाव अधिकारी डॉ. छगन भाई पटेल ने अभाविप के 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन में दोनों पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करते हुए उन्हें पदभार ग्रहण कराया। डॉ. पटेल के अनुसार दोनों पदाधिकारियों का यह कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा।

डॉ. नागेश ठाकुर मूलतः हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जोगिन्दर नगर से हैं, इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। भौतिकशास्त्र में शोध कार्य (पीएचडी) पूरा करके उसी हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला में ये प्राध्यापक हैं। विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर इनका गहन अध्ययन है, साथ ही तिब्बत समस्या, कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवाद, युवाओं के जीवन में नैतिक मूल्यों एवं आचार आदि विषयों पर भी समान रूप से अधिकार रखते हैं। डॉ. ठाकुर हिमाचल प्रांत में वामपंथी आंदोलन को परास्त करते हुए राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हुए हैं। कार्यपद्धति एवं कार्यकर्ता निर्माण में हिमाचल ने इनके मार्गदर्शन में नये मानक स्थापित किये। प्राध्यापक के नाते भी शोध स्तर पर वे सक्रिय हैं तथा भौतिकशास्त्र में इनके अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में 85 अंतर्राष्ट्रीय पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। विद्यार्थी परिषद् में इन्होंने पूर्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई से लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदि जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। वर्ष 2004 से 2007 तक वह अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

श्री विनय बिदरे मूलतः कर्नाटक प्रांत के तुमकुर जिले के बिदरे गांव से हैं एवं विद्यार्थी जीवन से ही वर्ष 1998 से अभाविप के सम्पर्क में हैं। शिक्षा के स्तर पर इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ पत्रकारिता भी की है। पूर्व में श्री बिदरे तुमकुर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष एवं अभाविप के कर्नाटक प्रांत के प्रांत मंत्री एवं राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। इन्होंने कई सामाजिक एवं शैक्षणिक आन्दोलनों का सफल नेतृत्व भी किया है। कर्नाटक में छात्रों की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में भी इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में अनियमितता से लेकर जनजाति छात्रावासों की समस्याओं का गहरा अध्ययन कर विभिन्न छात्र आन्दोलनों का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। कर्नाटक राज्य में महिला सुरक्षा जैसे आन्दोलनों में भी इनकी सहभागिता रही है। वर्ष 2014 में भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय द्वारा चीन गये प्रतिनिधिमंडल में सदस्य के रूप में श्री विनय बिदरे भी शामिल रहे। वर्तमान में श्री बिदरे कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्रीय सहसंगठन मंत्री के रूप में कार्य देख रहे हैं। ■

अभाविप के विदर्भ कार्यालय का उद्घाटन

नागपुर। राष्ट्रप्रेम से प्रेरित युवा ही विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। देश की प्रगति तभी सम्भव है जब युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो। राष्ट्रप्रेम से प्रेरित ऐसे अधिकतम युवाओं को तैयार करने की जरूरत है क्योंकि भारत युवा सम्पन्न देश है। इस दिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् बेहतर कार्य कर रहा है। उक्त बातें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने अभाविप के विदर्भ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कहीं। सीताबर्डी में अभाविप के विदर्भ विभागीय कार्यालय 'छात्रचेतना भवन' का उद्घाटन अंजनगाव सुर्जी के श्री देवकीनाथमठ के पीठाधीश आचार्य जीतेन्द्रनाथ महाराज ने किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का संगठन राष्ट्र के निर्माण की कड़ी होता है। ज्ञान के साथ–साथ चरित्र सम्पन्न बनाने से वह सम्भव है। व्यक्तिगत लक्ष्य पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय ध्येय की भावना निर्माण होने से ही राष्ट्र की प्रगति होती है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पिछले अनेक बरसों से राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत विद्यार्थी–युवाओं को बनाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा, 'मैं भी इसी अभाविप से सामने आया हूं इसलिए आज मैं यहां एक मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, अभाविप के एक कार्यकर्ता के तौर पर पहुंचा हूं।'

कार्यक्रम में जीतेन्द्रनाथ महाराज ने कहा कि देव, धर्म और देश को एक विचारधारा मानकर काम करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। देश, समाज और धर्म सभी क्षेत्र में काम करने वाला नेतृत्व तैयार करने का कार्य अभाविप कर रहा है। अभाविप के माध्यम से रामभाऊ म्हालगी प्रबोधन जैसी संस्था नागपुर में ही बननी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय संचेती, श्रीहरि बोरिकर और सुनील आंबेकर ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर 'छात्रचेतना विशेषांक' का लोकार्पण भी हुआ।

■

अभाविप के प्रदूषण मुक्त नर्मदा अभियान का दिखा असर

नर्मदा तट का सर्वे कर अभाविप ने न्यायालय में लगाई थी याचिका

धरमपुरी। नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा वर्ष 2013 में शुरू की गयी कवायद का असर दिखाई देने लगा है। दो वर्ष पूर्व परिषद् की विकासार्थ विद्यार्थी शाखा (एसएफडी) द्वारा गत 7 से 21 फरवरी तक नर्मदा अध्ययन यात्रा निकाली गयी थी। इसमें छात्रों के दल ने नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से विसर्जन स्थल भरुच (गुजरात) तक नर्मदा के विभिन्न तटों का सर्वे किया था। सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गयी थी, जिसमें नर्मदा में फैल रहे प्रदूषण के लिए प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (टीएनजी) भोपाल में याचिका लगाई गयी थी। याचिका पर कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया गया।

कोर्ट से सूचना पत्र मिलने के बाद मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड हरकत में आया। बोर्ड द्वारा तत्काल नर्मदा तटों पर सर्वे, प्रदूषण की स्थिति, जागरूकता अभियान, रैलियां, दीवार लेखन आदि के कार्य शुरू किये गये। वहीं नर्मदा तट पर आने वाले नगरीय निकायों को भी तटों की साफ–सफाई व अन्य कार्यों के लिए निर्देश जारी किये गये। जागरूकता अभियान में तो बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की व जनता से नर्मदा में प्रदूषण न फैलाने की अपील की। इसी तारतम्य में शहरों के नालों के गंदे पानी को रोकने के लिए भी योजना पर कार्य शुरू हुआ, जो शहर के गंदे नालों के उपचार संयंत्र के रूप में सामने आने वाला है। जिसके पश्चात् संयंत्र के माध्यम से नाले का गंदा पानी उपचारित होकर नर्मदा में पहुंचेगा।

सर्वे के अलावा परिषद् द्वारा गत वर्ष 21 फरवरी को धरमपुरी के नर्मदा तट पर धरना दिया गया था। इसमें परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीहरि बोरिकर, मध्य भारत प्रांत के सहसंगठन मंत्री राकेश पटेल सहित परिषद् के कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे। वहीं इस वर्ष 20 मई को अभाविप द्वारा नगर के गंदे नाले के समीप तपती गर्मी में करीब दो घंटे तक धरना दे तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया था। इसमें नर्मदा को प्रदूषण से बचाने की मांग की गयी थी।

विद्यार्थी परिषद की नर्मदा अध्ययन यात्रा के संयोजक व एसएफडी प्रमुख सचिन दवे थे, जो वर्तमान मे उक्त शाखा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने बताया कि दल में कुल 32 छात्र–छात्राएं शामिल हुए थे। ये छात्र वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, समाज शास्त्र व भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थी थे। दल ने नर्मदा तटों पर जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण, जलीय व तटीय जीव, तटीय वन औषधियों, धार्मिक आस्था व घाटों की स्थिति, बाढ़ प्रभावित व पुनर्वास क्षेत्र, नर्मदा की सहायक नदियों, नर्मदा पर स्थित बांधों व सरकार द्वारा की गयी पहल आदि विषयों पर अध्ययन किया था। दल द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर तैयार रिपोर्ट के माध्यम से ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में याचिका दायर की थी।

प्रो. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार

पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा हम सभी का : इम्तियाज अली

प्रो. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2015 हेतु युवा पुरस्कार चयन समिति द्वारा श्री इम्तियाज अली (भोपाल, मध्य प्रदेश) का चयन किया गया। श्री इम्तियाज अली को यह पुरस्कार 'सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्थान' के जरिये प्लास्टिक– ठोस अनुपयोगी सामग्री का प्रबंधन एवं कूड़ा बीनने वालों के उत्थान परियोजना की परिकल्पना की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया।

पुरस्कार ग्रहण करने के पश्चात् अपने सम्बोधन में श्री इम्तियाज अली ने कहा कि वर्तमान में प्लास्टिक का उपयोग इस कदर हमारी जीवनशैली में जुड़ गया है कि उसे अलग कर पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम इसके उपयोग और निष्पादन का कार्य सही ढंग से किया जाए ताकि पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। उन्होंने बताया कि कूड़े–कचरे में फेंके जाने वाले प्लास्टिक आदि वस्तुओं को गाय व अन्य जानवर चारे के साथ खा जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। सार्थक समूह द्वारा किये गये सर्वे में स्पष्ट हुआ है कि मारे जाने वाले जानवरों के आमाशय में कुल 20 किलो तक प्लास्टिक विभिन्न तौर पर मिले हैं। श्री अली ने बताया कि वर्ष 2008 में उच्चतम न्यायालय ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर रोक लगायी थी इसके बावजूद बाजार में सामान्य तौर पर यह उपलब्ध होते हैं। ऐसे में हमारी संस्था सार्थक ने एक पहल करते हुए कि इन प्लास्टिक कचरे को बीनकर अलग तरीके से इसका निष्पादन करेंगे ताकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस पर कार्य शुरू किया। साथ ही हमारे कार्य में कूड़ा बीनने वाले भी सहयोगी हुए जिससे उन्हें रोजगार मिला और हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए साथी।

भारत सरकार में केन्द्रीय मंत्री एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार प्रयासरत है। ऐसे में जहाँ तक बात प्लास्टिक पैकेट्स से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की है तो श्री इम्तियाज अली का प्रयास काफी सराहनीय है। इस प्रकार की मंशा के साथ हम सभी को आगे आना होगा तभी समाज और देश को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि वैसे तो पर्यावरण को लेकर सबकी चिन्ता जायज है पर प्लास्टिक का उपयोग इस कदर हमारे जीवन में हावी है कि उसे नकारना भी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि उनका विभाग भी प्लास्टिक कोटेड उत्पादों के विकास और वृद्धि पर कार्य करता है।

इससे पूर्व पुरस्कार प्रदान समारोह की शुरुआत अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने प्रो. यशवंतराव केलकर जी के जीवन परिचय को सबके समक्ष रखते हुए की। इस दौरान ममता यादव ने कहा कि प्रो. केलकर केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि परिषद् की पद्धति के मानक भी हैं और हमारे प्रेरणास्रोत भी। उन्होंने कहा कि जब सकारात्मक सोच के साथ परिषद् के कार्यकर्ता अपने उद्देश्य में लगते हैं तब लगता है कि प्रो. केलकर जी के शब्द हममें और हमारी पद्धति में जीवित हैं। ■

प्रस्ताव क्र. 1

शिक्षा की समग्र एवं व्यापक नीति- समय की आवश्यकता

भुवनेश्वर ओडिशा में संपन्न अभाविप के 61 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित

देशभर में नई शिक्षा नीति पर व्यापक चर्चा–परिचर्चा होना एक सुखद अनुभव है। सामान्य विद्यार्थी से लेकर अध्यापकों व शिक्षाविदों तक सभी के द्वारा देश में शिक्षा जगत में जुड़ रहे इस नये अध्याय की रचना में अपना योगदान दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विषय में अभाविप का मानना है कि शिक्षा नीति को मात्र पाठयक्रमों या मूलभूत संरचना तक ही सीमित न मानकर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास व शिक्षा के प्रति योग्य वातावरण के निर्माण के रूप में देखा जाना आवश्यक है। अभाविप शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की पक्षधर है।

अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए सरकारी संस्थाओं में सुधार आवश्यक है। विशेषतः सभी नियामक संस्थाओं के कार्यों में एकरूपता लाई जानी चाहिए। कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से लेकर मानविकी विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय होना चाहिए। विद्यार्थी समाज–जीवन से जुड़े व सामाजिक संवेदना का बीज उनमें प्रस्फुटित हो ऐसे प्रयास होने चाहिए। जमीन, समाज व संस्कृति के प्रति उनमें संवेदना उकेरना भी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा को पास–फेल सिस्टम से ऊपर उठाकर व्यक्तित्व के समग्र विकास का वाहक बनाने का प्रयास होना चाहिए।

सस्ती, गुणवत्तापूर्ण व सर्वसुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अभाविप का यह 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन देश में लगातार बढ़ते शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून की अपनी मांग दोहराता है। साथ ही शिक्षा क्षेत्र के हित में केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। वर्तमान समय में, निजी शिक्षा के महत्त्व व भूमिका को समझते हुए सुशासन की नीति का इन संस्थानों में भी प्रसार होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मात्र अभियान न चलाकर उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखकर एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता है। अभाविप प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराने की मांग करती है।

जाति, लिंग, गरीबी और भौगोलिक आधार पर पिछड़े विद्यार्थियों को समान अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिए। साथ ही, भारतीय मेधाओं व प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें उचित स्तर पर सम्मान व छात्रवृत्ति द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अपने स्थापना काल से ही भारतीय शिक्षा को भारतीय मूल्यों के अनुरूप संचालित करने की मांग करती रही है। नई शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत का गौरवशाली इतिहास सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, वर्तमान सरकार द्वारा महापुरूषों पर डाक–टिकट जारी किए गए हैं। अभाविप इस पहल का स्वागत करती है और यह मांग करती है कि महापुरूषों के व्यक्तित्व व कृतित्व को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अभाविप का यह सुविचारित मत है कि नालंदा व तक्षशिला की भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर वर्तमान में विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के अच्छे पाठ्यक्रमों से प्रेरणा लेकर देश के युवाओं में आत्मगौरव व सर्वआयामी ज्ञान का संचार हो, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। संविधान के दायरे में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को सभी धर्मों की जानकारी मिल सके।

अभाविप का मत है कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। सरकारी शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायी जाए व सभी स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाये। परिषद् का मानना है

कि देश के समग्र विकास हेतु कृतसंकल्प सरकार का यह राष्ट्रीय कर्तव्य है कि वो शिक्षा क्षेत्र हेतु पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करें। अभाविप का यह 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन केन्द्र सरकार से पुनः यह पुरजोर मांग करता है कि बजट का दसवां हिस्सा या जीडीपी का 6 फीसदी भाग शिक्षा पर खर्च किया जाए।

अभाविप देशभर के शिक्षार्थी, शिक्षक व शिक्षाविदों का आह्वान करती है कि वे अपने सुझावों के माध्यम से एक समग्र शिक्षा नीति हेतु ठोस पहल करें। अभाविप देशभर में प्राप्त सुझावों व चर्चा के पश्चात् एक प्रस्ताव शीघ्र ही सरकार को सौंपेगी। अभाविप सरकार से मांग करती है कि पूर्व नीतियों के व्यावहारिक अनुभवों से सीख लेते हुए नई शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन भी सुनिश्चित कर शिक्षा–जगत व जनमानस की अपेक्षाओं को पूरा करें।

प्रस्ताव क्र. 2

आतंकवाद व छद्म धर्मनिरपेक्षता के भारत विरोधी गठजोड़ के खिलाफ एकजुट हो देश

फ्रांस के पेरिस और माली के बामाको में विगत दिनों हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को पुनः हिलाकर रख दिया है और दुनिया के कुछ देशों ने आतंक का पर्याय एक मजहब को ही मानते हुए उसके विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है परंतु अभाविप का यह दृढ़ मत है कि भारतीय मान्यता के अनुसार कुछ कट्टरपंथियों के कारण से पूरे मजहब को आतंकवाद के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अलकायदा के बाद आई.एस. आई.एस. ने विश्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। विश्व के अनेक देशों के साथ भारत आतंकवाद का सर्वाधिक शिकार रहा है। आई.एस.आई.एस जैसे आतंकी संगठन से भारत के एक वर्ग विशेष के कुछ युवाओं का संपर्क में रहना चिंता का विषय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिंसा एवं आतंकवाद विरोधी सारी शक्तियां अपने सभी मतभेद भूलकर भारत समेत दुनिया में चल रहे आतंक के विरुद्ध एकजुट हों और इस आतंकवाद रूपी दानव का समूल विनाश करें। एक तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी तरफ ऐसी विकट परिस्थिति में भारत के छद्म सेकुलर बुद्धिजीवी व अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में आकण्ठ डूबे राजनेता प्रत्यक्ष रूप से देश की सुरक्षा एवं अखण्डता को अस्थिर करने का षड्यंत्र करते हुए भारत में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी एवं अलगाववादी समूहों का संरक्षण करते दिख रहे हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु–दण्ड घोषित आतंकवादियों अफजल गुरु, अजमल कसाब, याकूब की फांसी पर छाती पीटना, आतंकी घटनाओं को प्रतिक्रियाजन्य बताना, बिहार चुनाव से पूर्व आकस्मिक घटना को आधार बनाकर देश में असहिष्णुता का ढोंग करना, विदेशी संस्थाओं के द्वारा पोषित तथाकथित बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार लौटाना, कांग्रेस नेताओं द्वारा पाक में भारत विरोधी बयान देना यह स्पष्ट करता है कि देश में एक ऐसा नापाक गठजोड़ बन गया है जो भारत की सहिष्णुता की वैश्विक पहचान के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अभाविप का यह 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे तत्त्वों की ओछी व घिनौनी हरकत की कठोर शब्दों में भर्त्सना करता है।

विगत लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी ताकतों की विजय के साथ ही वैश्विक क्षितिज पर भारत के उभार से बौखलाए राष्ट्रविरोधी गठजोड़ द्वारा अचानक देश में असहिष्णुता का राग अलापना अत्यंत निंदनीय है। शासकीय एवं विदेशी संस्थाओं (फोर्ड फाउन्डेशन, ग्रीन पीस जैसी संस्थाओं) के धन पर केन्द्र सरकार द्वारा रोक लगा देने से उस धन पर पोषित छद्म सेकुलर बुद्धिजीवी और तथाकथित साहित्यकार अचानक बौखला उठे हैं। उन्हें देश में लगे आपातकाल के समय लोकतंत्र का गला घोंटने, अपने

ही देश में शरणार्थी बनने को विवश किये गये 3 लाख कश्मीरी हिन्दुओं के नारकीय जीवन, 1984 में 3000 से अधिक सिखों की हत्याओं, सिंगुर, नंदीग्राम की पाशविक घटनाओं, पश्चिम बंगाल व केरल में कम्युनिस्ट शासन के दौरान विरोधी विचारों के कार्यकर्ताओं पर ढाए गए जुल्म व उनकी बर्बर हत्याओं जैसी अनेक घटनाओं पर असहिष्णुता क्यों नहीं दिखाई पड़ी ? बिहार चुनाव से ठीक पहले देश में बढ़ रही असहिष्णुता के नाम पर मचाई जाने वाली शोर अचानक चुनाव परिणाम आते ही थम सी क्यों गयी? इससे यह ज्ञात होता है कि इन सबके पीछे निश्चित ही कोई न कोई षड्यंत्र है।

वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रविरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के ये सिपहसलार भारत में अशांति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। ये राष्ट्रविरोधी तत्त्व इतने उच्छृंखल हो चुके हैं कि निर्दोष नागरिकों के हत्यारों राष्ट्रघाती आतंकवादियों के लिए आधी रात को मा. सर्वोच्च न्यायालय को खोलने के लिए मजबूर करते हैं, पाकिस्तान में जाकर सम्प्रभुत्ता विरोधी बयान देते हैं और इन आततायियों के समर्थन में अत्यंत घृणित तरीके से एक स्वर में चिल्लाने लगते है। Save Dog- Save Tiger पशु प्रेम व मानवता की पहचान है परन्तु Save Cow पर सांप्रदायिकता का शोर मचाना व कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन की बात कहना, यह कौन–सी मानसिकता है? इस प्रकार के विकृत मानसिकता व सोच वाले तथाकथित प्रगतिशील लोग कहीं न कहीं लगातार राष्ट्रवाद को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं।

अभाविप का यह 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन देश के राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, युवाओं व छात्र–छात्राओं से आह्वान करता है कि वे इस अपवित्र गठजोड़ को समझते हुए इसके विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लें। साथ ही देश की छात्र–युवा शक्ति से अपेक्षा करता है कि वह सभी महाविद्यालयों–विश्वविद्यालयों से लेकर समाज में वैचारिक बहस प्रारंभ करें और राष्ट्रविरोधी गठजोड़ को परास्त कर राष्ट्रवादी विचार को स्थापित करें।

प्रस्ताव क्र. 3

पूर्वोत्तर के विकास में छात्र-युवा नेताओं की भूमिका

पूर्वोत्तर विविधता, बहु–संस्कृति व खनिज संपदा के साथ ही प्राकृतिक सुन्दरता का अनुपम क्षेत्र है। अभाविप ने सदैव इस क्षेत्र के विकास, सुरक्षा तथा यहां की विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास किया है।

अभाविप ने पूर्वोत्तर के विस्तृत अध्ययन के आधार पर भारत के शेष राज्यों से सीधा संवाद छात्र–छात्राओं के द्वारा हो, इसके लिए अनूठा उपक्रम SEIL 1966 में प्रारंभ किया। आज SEIL अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस प्रकल्प के माध्यम से पूर्वोत्तर की भौगोलिक जानकारी, आतंकी संगठनों का प्रभाव, विकास, शिक्षा में पिछड़ता पूर्वोत्तर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को देश व पूर्वोत्तर के समक्ष गंभीरता से रखने का प्रयास किया है। अभाविप का यह सुविचारित मत है कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना सम्पूर्ण भारत का विकास संभव नहीं है। और पूर्वोत्तर के विकास में उस क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।

अभाविप ने SEIL के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर SEIL के अनुभव के आधार पर पूर्वोत्तर के छात्र / युवा संगठनों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। दिल्ली में 3 अक्टूबर को आयोजित पूर्वोत्तर छात्र–युवा संसद में भाग लेने वाले

शेष पृष्ठ क्र.23 पर

झलकियां ...61 वें राष्ट्रीय अधिवेशन की

प्रस्तावक

अनुमोदक

युवा पुरस्कार समारोह के अतिथि केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करती सुश्री गीतांजली जैना साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नागेश ठाकुर

राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री जी. लक्ष्मण को स्मृति चिह्न प्रदान करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिद्रे

राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री श्रीनिवास संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनय बिद्रे संबोधित करते हुए

झलकियां ...61 वें राष्ट्रीय अधिवेशन की

प्रस्ताव सत्र के दौरान मंच पर उपस्थित छात्र नेता

गटशः चर्चा लेते हुए श्री गोपाल शर्मा

गटशः चर्चा चलाते हुए श्री आनंद रघुनाथन

गटशः चर्चा लेते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा

गटशः चर्चा लेते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिन्द मराठे

झलकियां ...61 वें राष्ट्रीय अधिवेशन की

भगवान श्री जगन्नाथ जी

भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा

उत्कलमणी गोपबन्धुदास सभागार के मुख्य प्रवेश द्वार की साज-सज्जा

श्री जगन्नाथ जी के 32 रूपों की आकर्षक प्रदर्शनी

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्मारक प्रदर्शनी का भव्य प्रवेश द्वार

प्रदर्शनी का अवलोकन करती छात्रा

झलकियां ...61 वें राष्ट्रीय अधिवेशन की

भव्य सभागार

जनजाति मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम

ध्वजारोहण के पश्चात वन्दे मातरम् गाती छात्राएं

पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन करते केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान

पृष्ठ क्र.16 का शेष

सभी छात्र–युवा संगठनों के प्रतिनिधियों का अभाविप का यह 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2015 अभिनन्दन व स्वागत करता है।

इन प्रतिनिधियों द्वारा न केवल पूर्वोत्तर के विकास अपितु भारत के विकास और सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए संकल्प लेना ऐतिहासिक स्वागत योग्य प्रयास है। इस छात्रनेता–युवा संसद में जिस प्रतिबद्धता व जिम्मेदारी के साथ सभी ने न्यूनतम साझा संकल्प दोहराया, इस संकल्प से पूर्वोत्तर के विकास हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होगा ऐसा विश्वास सभी छात्र नेताओं ने जताया, विद्यार्थी परिषद् इसको बड़ी उपलब्धि मानती है।

अभाविप SEIL के गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव के साथ ही आगामी समय में पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सभी कार्यकर्ताओं व समाज के सामने अपने संकल्प को दोहराती है।

• राष्ट्रीय एकता, अखंडता और पूर्वोत्तर में समुचित विकास के लिए अनुकूल माहौल बने इस हेतु अभाविप हमेशा प्रतिबद्ध होकर आगे भी सक्रियता से कार्य करती रहेगी।

• शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में सहयोग करना हमारी प्राथमिकता होगी।

• सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और पूर्वोत्तर के विकास हेतु सामूहिक प्रयास।

• नशा–मुक्त पूर्वोत्तर

• भ्रष्टाचार–मुक्त पूर्वोत्तर

• हिंसा–मुक्त पूर्वोत्तर

• युवाशक्ति का विकास– ध्येय में रखकर सतत् सामूहिक प्रयासों का आग्रह हो।

• भारत के अन्य राज्यों में पढ़ाई कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए देशभर में भयमुक्त और सुरक्षित माहौल का निर्माण हो।

• पूर्वोत्तर में शान्तिपूर्ण तथा जीवन यापन हेतु अनुकूल माहौल निर्माण करना यह सबका सामूहिक प्रयास बने।

अभाविप का 61 वां राष्ट्रीय अधिवेशन केन्द्र सरकार व पूर्वोत्तर की सभी राज्यों से मांग करता है कि पूर्वोत्तर के समग्र विकास की व्यापक नीति बनाकर देश के विकास में पूर्वोत्तर की भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अभाविप देश के नागरिकों, छात्र–युवाओं से आह्वान करती है कि SEIL द्वारा चलाये जा रहे "पूर्वोत्तर को जानो–भारत को जानो", अभियान में सहभागी हों तथा वहां की समस्याओं को समझकर उनके समाधान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अभाविप के छात्रों–युवाओं से आह्वान करती है कि वे देश विरोधी ताकतों के विघटनकारी मंसूबो को पहचानकर उनके विरुद्ध एकजुट होकर उनका प्रतिकार करें और पूर्वोत्तर में SEIL द्वारा चलाई जा रही विभिन्न रचनात्मक व विकासात्मक गतिविधियों में अपनी सहभागिता प्रदान करें, जिससे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

अभाविप का मोबाइल ऐप

डाउनलोड

करने की लिंक आपको

ABVP के

अधिकारिक अकाउंट

http://www.facebook.com/ABVPVOICE

https://twitter.com/abvpcentral

पर और वेबसाइट

www.abvp.org

पर भी उपलब्ध रहेगी।

प्रस्ताव क्र. 4

पर्यावरण संरक्षण पर प्रभावी नेतृत्व करे भारत

मानव और पर्यावरण का परस्पर अन्तः सम्बन्ध रहा है परंतु 18 वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रान्ति के आरम्भ से मानव ने प्रकृति का शोषण कर पर्यावरण को उसके अनुकूलन क्षमता से कहीं अधिक प्रभावित किया है। विश्व में इस औद्योगिक क्रांति के पुरोधा विकसित देशों ने पूंजीवाद पर आधारित उपभोगवादी वृत्ति का प्रचार किया, जिससे आज वैश्विक पटल पर पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक ताप एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे केंद्रीय विषय बने हैं।

आईपीसीसी की 2007 की रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 1970 से 2004 के मध्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 70 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2011 की ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में ओईसीडी सदस्य विकसित देशों ने औसतन 10 टन कार्बन–डाई–आक्साइड प्रतिव्यक्ति उत्सर्जित किया जबकि उसी वर्ष में भारत ने लगभग 1.5 टन प्रतिव्यक्ति उत्सर्जित किया।

आगामी 30 नवम्बर 2015 से पेरिस में प्रारंभ हो रहे 'संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन अधिवेशन' में विकसित राष्ट्र कार्बन उत्सर्जन पर कमी लाने हेतु नियम गढ़ने जा रहे है, जिसमें गरीब, कमजोर एवं विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाना विकसित राष्ट्रों की कुटिल नीति है। विकसित राष्ट्र अपना कार्बन एवं अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए तैयार नहीं है तथा अविकसित व विकासशील देशों पर उचित स्तर तक कार्बन उत्सर्जन न करने का दबाव बनाकर उनको पिछड़ा ही रहने देना चाहते है ताकि अविकसित व विकासशील देशों में उनके उत्पादों के उपभोग विश्वभर में सुनिश्चित रहें। विकसित देशों को इसी दोहरे मापदंड की नीति से समाधान का मार्ग अत्यंत जटिल एवं दीर्घकालीन हो रहा है।

अभाविप का यह 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन भारत सरकार के आह्वान करता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के इस जलवायु परिवर्तन अधिवेशन से विकासशील एवं कमजोर देशों के हितों की रक्षा करते हुए सक्षम नेतृत्व दे। जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर औद्योगिक देशों की हठवादिता जिसमें वे अपने अति–भोगवाद के जीवनस्तर को नियंत्रित नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी ओर अन्य देशों में जीवन स्तर सुधार सके, इसके लिए ग्रीन तकनीकि देना भी उन्हें नागवार गुजर रहा है। जिसके लिए वे बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे नियमों की दुहाई देकर इन तकनीकों पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते है, साथ ही विकासशील देशों को वे अपने पुराने उत्पादों का डम्पिग ग्राउंड बनाते है।

अभाविप मानती है कि भारत को समय–समय पर विकासशील राष्ट्रों के हित के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण, जैव–विविधता सम्पन्न तथा नैसर्गिक जीवन के प्रति श्रद्धा रखने वाली जीवन पद्धति के साथ विकास करने वाले राष्ट्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और विश्वमंचों पर उनकी सराहना सुनिश्चित करनी चाहिए।

विद्यार्थी परिषद् का स्पष्ट मत है कि भारत प्राचीन परम्पराओं के अनुसार कम प्रदूषण तथा अनुकूलन की क्षमता को विकसित करके, विकास का उपयुक्त मॉडल विश्व को प्रस्तुत करें तथा अंतरराष्ट्रीय दबाव से अलग जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मापदण्ड स्थापित करें।

अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन देश के विद्यार्थियों तथा छात्र संघों से अपील करता है कि वे परिसरों में पर्यावरण संरक्षण की सकारात्मक बहस खड़ी करें तथा समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागृत करें।

■

युवा भारत समर्थ भारत

राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानन्द जयन्ती) के अवसर पर राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका के विशेषांक 'युवा भारत - समर्थ भारत' का विमोचन माननीय सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले के करकमलों द्वारा 15 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में होगा।

150 पृष्ठ का संपूर्ण रंगीन कलेवर एवं सामग्री की दृष्टि से समृद्ध यह अंक संग्रहणीय है।

आगामी विशेषांक

'युवा भारत-समर्थ भारत'

की प्रतियां बुक कराने के लिए सम्पर्क करें...

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
011- 23216298, 9899108256

साक्षात्कार

'भारत केन्द्रित शिक्षा नीति के लिए परिषद संघर्षरत'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री और अब राष्ट्रीय महामंत्री तक का सफर तय करने वाले श्री विनय बिदरे मूलतः कर्नाटक प्रांत के तुमकुर जिला के बिदरे गांव के हैं। वर्ष 1998 से वह अभाविप के संपर्क में आये। अपने शैक्षणिक जीवन में इन्होंने कई आन्दोलनों का सफल नेतृत्व भी किया। इसके अलावा विनय बिदरे 2014 में भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय द्वारा चीन भेजे गये प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे। वर्तमान में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय सहसंगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन में **नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे से राष्ट्रीय छात्रशक्ति संवाददाता ने बात की। प्रस्तुत हैं बातचीत के अंश...**

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मिली नयी जिम्मेदारी को आप किस तरह देखते हैं?

परिषद के प्रति मेरी जिम्मेदारी पहले भी थी और आगे भी रहेगी। जहाँ तक नई जिम्मेदारी की बात है तो अभाविप कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने के लिए नित नये कार्यभार देता है ताकि कार्यकर्ता का पूर्ण विकास हो। मैं इस नयी जिम्मेदारी को भी इसी मद में देखता हूँ।

अभाविप के विस्तार कार्य की क्या स्थिति है और जिन राज्यों में अभाविप की पहुँच कम है वहाँ के लिए परिषद की क्या योजनाएं हैं?

वर्तमान समय में विद्यार्थी परिषद की पहुँच देशभर में है। शायद ही कोई जिला होगा जहां अभी तक परिषद नहीं पहुंची है। हाँ यह हो सकता है कि कहीं–कहीं परिषद का कार्य थोड़ा कम होगा जिसके लिए योजनाएं बन रही हैं और जल्द ही वहाँ भी कार्य में गति आयेगी।

आने वाले दिनों में अभाविप के कार्य की दिशा क्या होगी?

शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ विद्यार्थी परिषद की प्रारम्भ से ही लड़ाई चल रही है। ऐसे में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में उन्नतीकरण की जरूरत है, जिसमें परिषद अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा बेहतर शिक्षण के संदर्भ में भारत केन्द्रित नई शिक्षा नीति को लेकर भी परिषद का प्रयास जारी है। जिसके जरिए युवाओं के भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास की जानकारी मिले, इसकी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

शिक्षा के स्तर में सुधार के अलावा और किन विषयों को परिषद प्रमुखता से उठायेगी?

शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनुचित व्यवहार (अनफेयर प्रैक्टिसेज) हैं जिसको रोकने के लिए एक केन्द्रीय कानून की जरुरत है। परिषद लगातार इस विषय को उठा रहा है। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं के बीच इंटर लिंकिग यानि आपसी जुड़ाव होना चाहिए, जिसके लिए एक एजुकेशन कमिशन की जरूरत है। इस संदर्भ में भी विद्यार्थी परिषद अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसे बाद में सरकार के पास भेजा जायेगा।

सामाजिक परिदृश्य में परिषद की क्या भूमिका है?

राष्ट्रवादी छात्र संगठन होने साथ ही अभाविप

सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। ऐसे में सामाजिक परिदृश्य में परिषद की भूमिका काफी अहम है। आने वाले दिनों में परिषद पूरे देश में एक सामाजिक सर्वेक्षण की योजना बना रहा है। इसके पीछे की मंशा पूरे देश की सामाजिक स्थिति को समझने की है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों और रिपोर्ट के आधार पर परिषद भविष्य की अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगी।

नई शिक्षा नीति को लेकर परिषद किस प्रकार आगे बढ़ रही है?

नई शिक्षा नीति को लेकर केन्द्र सरकार ने बहुत बढ़िया प्रयास शुरू किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। वर्तमान की शिक्षा नीति भारतीय मूल से काफी दूर है, ऐसे में परिषद चाहती है कि भारतीयता के भाव में समाहित एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार हो जिसमें देश के महान ऋषि–मुनियों और महापुरुषों के बारे में और उनके विचारों को प्रमुखता से बच्चों को बताया जाये। वैसे भी भारतीय शिक्षा नीति सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। सभी को पता चलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा से विश्वभर के लोग क्या सीख सकते हैं। आखिर हमारे पास पूर्व में नालंदा और तक्षशिला में विदेश से लोग सीखने ही तो आते थे तो फिर आज क्यों नहीं हम विश्व को शिक्षा दे सकते हैं।

जनजाति समुदाय के लोगों के लिए परिषद की क्या योजना है और किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं?

जनजाति समुदाय के विकास को लेकर परिषद अपने कार्य में लगातार लगा हुआ है। फिलहाल जनजातीय छात्रों को अवसर और छात्रवृत्ति मिले इसकी दिशा में अभाविप तेजी से आगे बढ़ रही है। शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक परिषद अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत है, ताकि जनजातीय छात्रों को सुलभता हो सके।

परिषद बराबर सभी को समान अवसर मिले यह बात कहती रही है, ऐसे में परिषद इस दिशा में क्या कदम उठा रही है?

सभी को समान अवसर मिले यह परिषद का सिर्फ कथन नहीं। परिषद इसके लिए लगातार काम भी कर रही है। इस दिशा में जनजाति छात्रों के साथ सामान्य छात्रों को अवसर मिले इसके लिए अभाविप आवाज बुलंद किये हुए हैं। जहाँ तक बात योजनाओं की है तो चिकित्सा छात्रों के लिए 'मेडिविजन' जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति–जनजाति व पिछड़े वर्ग के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिले इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान में आरक्षण का मुद्दा काफी उठ रहा है। ऐसे में समान अवसर की बातों को आरक्षण से नुकसान होगा क्या?

ऐसा नहीं है कि आरक्षण शब्द के प्रयोग से समान अवसर की भूमिका प्रभावित हो रही है। विद्यार्थी परिषद् आरक्षण की विरोधी नहीं है। मगर यह देखना होगा कि जिसे जितना मिलना चाहिए था क्या आरक्षण के बाद भी उसे वह मिल रहा है। अगर समूह विशेष को जरूरत से कम लाभ मिल पाया है तो उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। मगर इन सबके बीच समान अवसर की बात सभी के लिए जायज है और यह सबको मिलना चाहिए।

वर्तमान में असहिष्णुता और बीफ को लेकर काफी बवाल हुए हैं। इन मुद्दों पर अभाविप की क्या राय है?

कहाँ है असहिष्णुता और कौन उठा रहा है असहिष्णुता का मुद्दा। वो ऐसे कुछ लोग हैं जो जीवन को पूरी बेहतरी के साथ निर्वहन कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेकार के मुद्दे ढूंढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ राष्ट्रवादी विचारों की खिलाफत करनी है तो असहिष्णुता की बातें उठा रहे हैं। पिछले 30–40 सालों से ये लोग एक समूह के

लिए काम करते थे, मगर अब जब देश के लिए सोचने वाली एक सरकार सत्ता में आयी है तो उन्हें यह बात पच नहीं रही है। क्योंकि अब उन्हें भी देश के लिए काम करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला गौ मांस का भी है। लोग सिर्फ राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ कैसे क्या करें इसको लेकर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वैसे भी गाय को लेकर भीम राव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में भी कहा है कि गाय जैसे प्राणियों की हमें रक्षा के साथ उनका पोषण भी करना होगा।

जम्मू–कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर अभाविप क्या सोचती है और वहाँ परिषद की कार्यप्रणाली कैसी है?

जम्मू–कश्मीर में भी परिषद अपनी योजना पर काम कर रही है। वहाँ के हालात में परिवर्तन भी आया है और तेजी से राष्ट्रीय विचारधारा का प्रवाह हो रहा है। जो भी कुछ अलगाववादी लोग हैं उन्हें स्थानीय लोगों का बहुत कम समर्थन मिल रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण अच्छा है। एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन के तौर पर अभाविप लगातार लोगों से सम्पर्क कर शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में उनकी मदद का कार्य कर रही है। परिषद जम्मू–कश्मीर के लोगों को पूरी तरह से देश से जोड़ने की मंशा के साथ अपनी योजना पर बेहतर ढ़ंग से काम कर रही है।

पूर्वोत्तर के विकास के लिए अभाविप ने एक नया नारा 'लुक ईस्ट नहीं, लीड ईस्ट' दिया है। ऐसे में परिषद किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और उसकी क्या योजनाएं हैं?

विद्यार्थी परिषद पूर्वोत्तर में पिछले 50 सालों से बेहतर कार्य कर रहा है। छात्र अनुभव और अंतरराज्यीय जीवन दर्शन (इंटर स्टेट लिविंग) के नाते शिक्षा व संस्कृति से सबको जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं इस वर्ष सील (SEIL)का स्वर्ण जयंती वर्ष भी मना रही है, जिसके तहत 'पूर्वोत्तर को जानो भारत को जानो' शीर्षक के साथ कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। पूर्वोत्तर के सभी छात्र संगठनों को एक मंच पर लाने का काम भी विद्यार्थी परिषद ने किया है। बीते दिनों दिल्ली में पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद में इन सभी को एकत्र कर पूर्वोत्तर के विकास के लिए एकजुट प्रयास करने पर सहमति भी बनी है। परिषद के साथ मिलकर छात्र संगठनों ने नशामुक्त, हिंसामुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित पूर्वोत्तर की कल्पना पर काम करने की बात कही।

आज भी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं यह संदेह है कि अभाविप भाजपा का स्टूडेंट विंग है। ऐसे में परिषद कैसे खुद को एक स्वतंत्र छात्र संगठन के रूप में परिभाषित करेगी?

देखिये.. आज वर्तमान में हर कोई जानता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत विद्यार्थी परिषद के अपने कुछ मुद्दे हैं। ऐसे में परिषद के उठाये जाने वाले मुद्दों को भी राजनीतिक दल समर्थन या फिर उसी प्रकार के मुद्दों पर काम करती है तो आमजन उसे आपस में जुड़ा हुआ मानने लगते हैं। मगर हकीकत तो सभी को पता है कि विद्यार्थी परिषद सिर्फ छात्र हित और छात्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं को उजागर करने का काम करती है। परिषद के विचार और उनके कार्य की दिशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जरूर प्रभावित और पोषित है पर इसे भाजपा की छात्र इकाई कहना तथ्यात्मक भी गलत है।

युवाओं में व्यक्तित्व विकास और समाज उपयोगी कार्य करने को लेकर आप उन्हें क्या संदेश देंगे?

हमारा छात्र संगठन युवाओं के बीच सिर्फ डिग्री या किसी प्रमाण के लिए काम नहीं करता। बल्कि हमारा उद्देश्य छात्र हित के साथ उनमें राष्ट्रीय सोच विकसित करते हुए व्यक्तित्व विकास करना है। स्वामी विवेकानन्द जी ने भी कहा है कि शिक्षा के जरिए शिक्षित होने के साथ चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ परिषद काम करता है और एक सामान्य छात्र का आदर्शवान युवा के तौर पर निर्माण करता है। ■

शिक्षा पर संवेदनहीन बुद्धिजीवी

✍ अवनीश राजपूत

पिछले दिनों देश में असहिष्णुता का आगाज हुआ। लेखक हों या कलाकार, बुद्धजीवी हों या पत्रकार, सबकी नजर में भारत देश अब रहने के लायक नहीं रहा। यहां के अराजक माहौल में उनका दम घुटने लगा। इसकी परिणीति यह हुई कि कुछ लोगों ने अपना सम्मान लौटाया तो कइयों ने देश छोड़ने की घोषणा की। इस तरह एक और महीना बीता, बात आयी और गयी। अब देश में चारो तरफ शांति दिख रही है और किसी भी बुद्धजीवी को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है और न ही किसी मीडिया चैनलों में इसका सियापा सुनाई दे रहा है। देश की मानों सारी समस्याएं कलबुर्गी से शुरू होकर अखलाख पर ही खत्म हो गयीं। बिहार चुनाव के बाद इन बुद्धजीवियों की नजर में अब कोई समस्या बची ही नहीं है।

इन दिनों राजस्थान राज्य के कोटा शहर में एक अजीब सा माहौल बन चुका है। यहां आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र आये दिन आत्महत्या कर रहे हैं। बावजूद इसके इस मसले पर बुद्धजीवीयों की जुबान पर कर्फ्यू लग चुका है। शिक्षा के नीति–नियंताओं के चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं दिख रही है। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इससे वोटों की फसल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां समस्याओं का निर्धारण वोट बैंक के थर्मामीटर से किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी किसी खबर या घटना पर देश के पुरस्कृत लेखक, बुद्धिजीवियों, कलाकारों ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न आने की उम्मीद है। इनकी प्रतिक्रियाएं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक छात्र द्वारा वैदिक मन्त्रोच्चार और हवन–पूजन कर जन्मदिन मनाने के विरोध में तो आती हैं लेकिन शिक्षा से सीधे तौर पर जुड़े इन मसलों पर जुबान पर ताले लग जाते हैं।

एक ताजा आकड़े के अनुसार कोटा में 70 फीसदी छात्र डिप्रेशन के शिकार हैं। मनोचिकित्सक बताते हैं कि यहां हर साल लाखों छात्र कोचिंग करने पहुंचते हैं और औसतन केवल 3 से 4 हजार छात्रों को ही सफलता हासिल होती हैं, ऐसे में असफल छात्र डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसके चलते ऐसे मामलों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। छात्र–छात्राओं द्वारा की जा रही आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बाद नींद से जगी वसुंधरा सरकार अब जाकर हरकत में आयी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आनन–फानन में मुख्य सचिव को इस बाबत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं अब राज्य सरकार भी कोचिंग सेंटर के लिए गाइड लाइन बनाने पर विचार कर रही है।

आंकड़ों पर गौर करें तो देखेंगे कि पिछले एक वर्ष में कोटा में 19 और पांच वर्षों में यहां करीब 75 छात्र–छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले छह माह में खुदकुशी के 12 मामले सामने आए हैं। एक जनवरी 2015 से अब तक यहां करीब 17 छात्रों ने पढ़ाई के दबाव में आकर मौत को गले लगाया। सुसाइड के मामलों में इस शहर ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। 2014 के आकड़ों की बात करें तो दिल्ली में 45 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जबकि दिल्ली से लगभग एक चौथाई क्षेत्रफल में फैले अकेले कोटा शहर में भी 45 छात्रों ने आत्महत्या की। आंकड़ों के आधार पर साफ अंदाजा लगाया जा

सकता है कि पिछले साल के बाद अबकी बार भी आत्महत्या के मामलों में कोटा सबसे ऊपर है।

रेलवे के पूर्व अधिकारी और कथाकार प्रेमपाल शर्मा की माने तो इससे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा क्या हो सकता है, जब बच्चे कुछ आरोपित सपनों को पूरा न कर पाने की हताशा में मां–बाप, समाज, दोस्तों की टेढ़ी, व्यंग्य भरी नजरों से भयभीत होकर अपनी जान दे रहे हैं। आखिर दोष किसका है? बच्चों का तो कतई नहीं। वे तो कच्ची मिट्टी हैं जैसा ढालोगे, पकाओगे वैसा ही वे बनेंगे। दुनिया के सामने हमारे नेता तो इस बात पर इतराते हैं कि विश्व में सबसे युवा आबादी भारत में है लेकिन क्या इन युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पर्याप्त संसाधन और व्यवस्था है हमारे पास। कोई और देश होता तो शिक्षा से जुड़े इस गंभीर मसले पर पूरा समाज सड़कों पर उतर आता।

प्रतिस्पर्धा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने होंगे जो बच्चों को इतना मजबूत बनाएं कि जीवन में किसी परीक्षा में पास–फेल होना कोई मायने न रखे। बच्चों को विवेकानन्द, जगदीश बसु, महात्मा गांधी से लेकर प्रेमचंद की वे जीवनियां पढ़ाई जाएं जिनसे बच्चे जान सकें कि स्कूल या प्रतियोगिता में कुछ नंबरों के कम–ज्यादा होने से खास फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही बच्चों से ज्यादा उनके मां–बाप की मानसिकता को बदलना जरुरी है कि वे अपने खोखले उसूलों और नकली सपनों की खातिर क्यूं इन लाडलों की कुर्बानी देने पर तुले हुए हो। देखा जाए तो अधिकतर मामलों में अभिभावकों द्वारा बच्चों पर थोपे गये सपनों को पूरा न कर पाने की कसक आज इस तरह के माहौल को जन्म दे रही है।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब 'अंतिम उदारवादी' में 'महात्मा गांधी की मार्कशीट' नाम का रोचक लेख है। उस लेख के अनुसार स्कूल में महात्मा गांधी की उपस्थिति बहुत खराब रहती थी और वार्षिक परीक्षा में 45 से 55 प्रतिशत के बीच ही अंक मिलते थे। मैट्रिक परीक्षा में शामिल 3067 बच्चों में 799 उत्तीर्ण हुए, जिसमें गांधीजी 404 वें स्थान पर रहे। उन्हें 40 प्रतिशत अंक मिले थे। क्या दुनिया ने कभी गांधीजी की मार्कशीट या डिग्री देखने की कोशिश की? आज के मां–बाप तो खुदकुशी ही कर लें 40 फीसदी अंकों को देखकर।

देर से ही सही लेकिन अब इस मामले में जहां राज्यपाल कल्याण सिंह ने संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है वहीं अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी देशभर के कोचिंग संस्थानों के नियमन की तैयारी शुरू कर दी है। छात्रों पर मानसिक दबाव कम करने और फीस के मुताबिक कोचिंग संस्थानों में संसाधन और पढ़ाई का स्तर सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी रुड़की के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नेंस) के अध्यक्ष प्रो. अशोक मिश्रा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इस छह सदस्यीय समिति ने मंत्रालय से राष्ट्रीय स्तर पर नियामक संस्था के गठन की सिफारिश की है।

कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्राओं की आत्महत्या के मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रो. मिश्रा की अध्यक्षता में छह शिक्षाविदों की विशेषज्ञ समिति गठित कर इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के मौजूदा स्वरूप के साथ ही कोचिंग संस्थानों की जरूरत और उनमें पढ़ाई के पैटर्न की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। समिति ने अपनी प्राथमिक सिफारिशें मंत्रालय को सौंप दी हैं। समिति ने प्रवेश परीक्षाओं का पैटर्न बदलने के साथ ही कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए ऑल इंडिया कॉउंसिल फॉर कोचिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम (एआइसीसीईई) के गठन की सिफारिश की है। वक्त आ गया है जब देश के नीति–नियंता, राजनीतिक दल शिक्षा के मसले पर गंभीरता से विचार करें, वरना इतिहास और दर्शन की यह बात फिर सच होगी कि शासक बदलने से सत्ता का चरित्र नहीं बदलता। शिक्षा का तो कतई नहीं बदल रहा।

■

विद्यार्थी परिषद की इमारत की नींव थे अरुण भाई यार्दी

प्रा. अरुणभाई यार्दी अब अनन्त यात्रा पर हैं, पुरानी बीमारी के बाद पाँच नवंबर 2015 को उनका देहान्त हुआ। बच्चे, बुजुर्ग सभी के चहेते प्रज्ञावान प्राध्यापक अरुण भाई ने साधना में 'हल्लो यंग कैड़', 'अमर उद्गारो' और 'माटी की महक' के जरिए विचारों की महक फैलायी। छोटे जीवन प्रसंगों में प्रेम, मान–सम्मान, संवेदनशीलता, परोपकारिता, शील, चारित्र्य, नागरिकता और राष्ट्रप्रेम प्रकाशित करने की अद्भुत कला उनमें चरितार्थ थी। प्रासंगिक कथा द्वारा श्रोताओं की मार्मिकता को संवेदनाओं से सराबोर करने की कला में भी वे पारंगत थे। उसके बावजूद सरल, सहज, मार्मिक, मौन लेकिन विचार पुष्टि के प्रवर्तक, लेखक, प्रसंगों के द्वारा प्रेरणा देकर युवाओं को वैविध्यपूर्ण आदर्श जीवन के लिए तैयार करने वाला एक विरल व्यक्तित्व थे। उक्त बातें कर्णावती महानगर के सहकार्यवाह तेजसभाई पटेल ने स्व. अरुण भाई यार्दी की शोक सभा में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहीं।

बतादें कि, बीते 19 नवंबर 2015 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थी परिषद गुजरात प्रान्त के पूर्व प्रान्त प्रमुख स्व. अरुणभाई यार्दी को श्रद्धा–सुमन अर्पित करने हेतु श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। जिसमें अभाविप के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने सद्भावना प्रकट करते हुए अपनी बातों को रखा। इस दौरान, प्रान्त संघचालक मुकेश भाई मलकान एवं पश्चिम क्षेत्र के संघचालक ज्योतिभाई झाडेशिया द्वारा प्रेषित शोक संदेश पढ़ा गया।

स्व. अरुणभाई यार्दी के साथ काफी सालों का परिचय रहा है। उनसे जब भी मिलना होता था, हर वक्त कुछ नया सीखने को मिलता था। उनका कहना था कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं–युवाओं को कार्य के बारे में सही तरीके से समझना पड़ेगा। उन्हें ऐसा माहौल देना पड़ेगा। अभाविप भाग्यशाली है कि उसे अरुणभाई जैसे चिंतक–विचारक मिले। ईश्वर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे यही प्रार्थना है।

– सुनील आम्बेकर (राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अभाविप)

स्व. अरुणभाई का आशिर्वाद सदा हमको मिलता रहेगा। वो अभाविप की नींव के मुख्य आधार थे, जिन्होंने चाणक्य की तरह परिषद को अनेक विद्यार्थी कार्यकर्ता दिये। लेखन में उनका अमूल्य योगदान रहा। उनकी निर्देशन में हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रही है, लेकिन उनकी विदाई के बावजूद उनके कार्य हमें प्रेरणा देते रहेंगे। समाज के ऐसे सुधारक शिल्पी को परमात्मा अपने चरणों में जगह दे।

– प्रा. छगन भाई पटेल (प्रदेश अध्यक्ष, अभाविप, गुजरात)

पिताजी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे। अपने आदत के अनुसार पिताजी मुझे, मेरी पत्नी और माताजी सभी को प्रोत्सहित करने के लिए पत्र लिखा करते थे। दुख के क्षणों में अडिग और मजबूत बने रहने वाले पिताजी ने यह गुण हमारे अन्दर भी विकसित किया। एक अच्छा इंसान कैसे बना जाये ये हमे सिखाया। उन्होंने मुझे जीवनमूल्यों के बारे में बताया–सिखाया। पिताजी उनके विचार एवं लेखन के जरिए हमेशा हम सब में जीवित रहेंगे। **– अभिजित अरुणभाई यार्दी (स्व. अरुणभाई यार्दी के पुत्र)**

गर्व से कहो मैं हिन्दुस्तान की बेटी हूं -प्रो. चावला

लुधियाना। जियो शान से.. अपने पर फख्र करो कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं। अगर देश में लड़कियां न हो तो वह देश नहीं चलेगा। नारी शक्ति की धारणा मात्र ही समाज को संकल्पित और संयमित जीवन की दिशा देता है।

उक्त बातें पंजाब की पूर्व मंत्री प्रो. लक्ष्मीकांता चावला ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लुधियाना में आयोजित किये गये राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहीं। प्रो. चावला 'शक्तिशाली महिला, शक्तिशाली भारत' विषयक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमृता कौर गिल एवं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चंडीगढ़ की सदस्या डॉ. मंजीत कौर सहोता भी मौजूद रहीं।

प्रो. चावला ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि वह खुद 1980 से 1985 तक अभाविप की कार्यकर्ता रह चुकी हैं। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अच्छी लगने वाली चीजों को ही अच्छा कहें और बुरी लगने वाली चीजों को बुरा। अभिनेता अमिताभ बच्चन फैशन परेड के विज्ञापन में आए, अभाविप ने उसे बंद कराया। रोजाना पेपर में लड़कियों के बुरे विज्ञापन आते हैं, क्या हम में से किसी को शर्म नहीं आती। हमें यह बुरा क्यों नहीं लगता?

उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि कई मंदिरों में लड़कियों के जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें पैदा तो किसी औरत ने ही किया है। कन्या को देवी न बनाओ, बस इंसान बनकर जीने दो।

प्रो. चावला ने कहा कि कुछ दोष हममें भी हैं। राखी पर कभी किसी लड़की ने भाई से प्रण के रूप में यह लिया है कि वह हेल्मेट पहनेगा, ट्रैफिक नियमों का पालना करेगा। मेरा मानना है कि किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि वह खुद इसका पालना नहीं करती होंगी। अंग्रेजों के समय में हम गुलाम नहीं थे, मगर आज के समय में हम गुलाम होकर रह गए हैं। आज समय का बदलाव देखिए कि हम हर त्योहार पर दीया जलाते हैं और खुद अपने ही जन्मदिन पर दीपक बुझाते हैं।

एडिशनल डिप्टी कमीश्नर अमृता कौर गिल ने कहा कि महिला होने पर वह गर्व महसूस करती हैं। नारी सशक्तीकरण जरूरी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत है। हमारी संस्कृति धनी है। इस पर भी सभी को गर्व महसूस करना चाहिए न कि पश्चिमी संस्कृति देख प्रभावित होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते कहा कि मैंने शादी के बाद पीसीएस किया, जो कि काफी मुश्किल होता है। मेरे पति ने इसके लिए मुझे काफी सहयोग दिया है। उन्होंने सबसे अपील करते हुए कहा कि अपने में आत्मविश्वास रखो हर चीज इससे संभव है।

जालंधर से आई डॉ. सोनिया चावला ने कहा कि हर कॉलेज कैंपस में नारी सशक्तीकरण प्रकोष्ठ (CELL) होता है, जो कि यूजीसी की गाइडलाइन है। ■

मधेशी आन्दोलन और नेपाल में राजनीतिक हलचल का सच

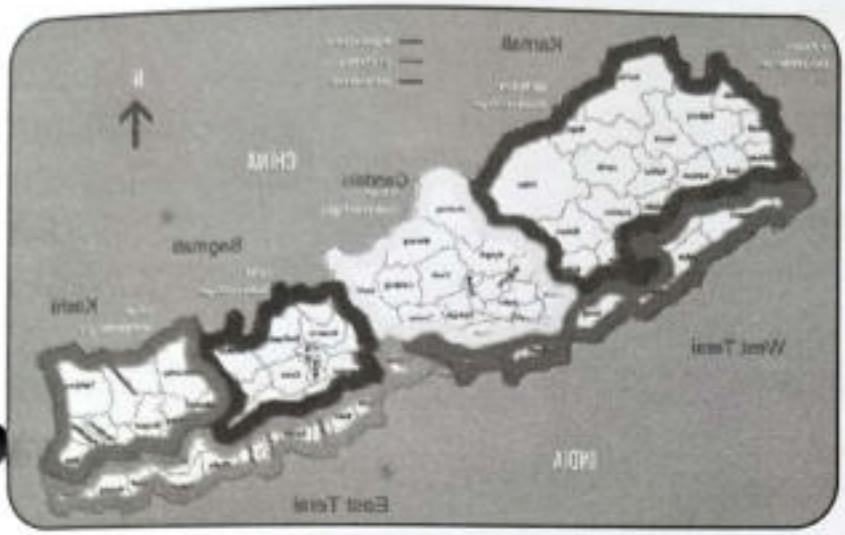

नेपाल की वर्तमान राजनीतिक समस्या, नवीन संविधान एवं मधेशी आन्दोलनों की स्थिति को लेकर हर ओर चर्चा का माहौल है। ऐसे में नेपाल के वर्तमान हालात और जनता व सरकार के बीच संवाद की स्थिति पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से खुलकर बात की प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद, नेपाल के संगठन मंत्री श्री दीपक अधिकारी ने। उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य के बारे बात करते हुए भारत–नेपाल संबंधों पर भी अपने विचार रखे।

नेपाल की समस्या को लेकर दीपक अधिकारी का कहना है कि वर्तमान में जो भी भयावह स्थिति बनी है उसके पीछे अकारण मांग और राजनेताओं द्वारा लिये गये गैरवाजिब फैसले हैं। सबसे बड़ी बात ये कि देश का संविधान उस समय आया जब पूरा नेपाल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था। ऐसे में लोगों पर संविधान की आड़ में मनमाने नियमों को थोपा गया। आपदा के दर्द से लोग उबर भी नहीं पाये थे कि नेपाल में आतंरिक आंदोलन शुरू हो गये। आंदोलन का मुख्य कारण संविधान सभा का आना रहा। श्री अधिकारी बताते हैं कि नेपाल सरकार ने गलत समय में संविधान लाकर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का काम किया। सरकार की प्राथमिकता जनता को मूलभूत सुविधा प्रदान करना और तबाह हुए इलाकों को पुनर्स्थापित करना था न कि विवादित ड्राफ्ट लाकर लोगों को अनावश्यक परेशानी में डालना।

आषाढ़ महीने में सरकार जो ड्राफ्ट लेकर आयी उसमें कई खामियां थीं। संविधान की प्रस्तावना में भी कुछ नकारात्मक बातों को जोड़ा गया। मसलन संविधान में समाजवाद उन्मुखी को जोड़ना, किसी भी व्यक्ति को धर्म से अलग होने का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और यौनिक उन्मुखीकरण जैसे मुद्दों को जोड़ना लोगों के विरोध का मुख्य कारक बना। पूरे मामले को लेकर नेपाल में विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले प्रस्तावना का विरोध किया। साथ ही परिषद ने सरकार व संविधान सभा को अपने सुझाव भी सौंपे। परिषद का कहना था कि किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना में निरकुंश, सामंती जैसे शब्दों का उल्लेख उसकी महत्ता को अप्रासंगिक बनाता है।

विरोध के बढ़ते स्वर के बीच सरकार ने सफाई दी कि धर्मनिरपेक्षता आदि को लेकर फैसला नास्तिक लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सरकार ने लोगों से संविधान सुझाव संकलन हेतु आम राय भी मांगी। नेपाली जनता और आंदोलनकारियों ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें– संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रधानमंत्री का चुनाव परोक्ष होने जैसे मुद्दों पर विरोध जताया गया। जिसके बाद सरकार ने बिना नाम के सीमांकन करने का आश्वासन दिया और कहा कि संघीयता को परिभाषित करने के लिए एक कमेटी बनाकर समाधान निकाला जाएगा। परंतु बाद में सरकार अपने वादों से मुकर गयी, जिससे जनता आक्रोशित हो गयी। विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि सरकार यह स्पष्ट करे कि वो किस आधार पर धर्मनिरपेक्षता लाना चाहती है, धार्मिक आधार पर,

राजनीतिक आधार पर, सुरक्षा के आधार पर या फिर कार्मिक आधार पर। इसी समय विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। जिसमें एक मधेश एक प्रदेश, प्रांतों का सीमांकन निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर करने, मधेशियों को बराबरी का दर्जा दिये जाने, संविधान में मधेश और पहाड़ का स्पष्ट उल्लेख करने तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक मधेश बनाये जाने की मांग उठायी गयी।

वहीं, नेपाल के अंदर उथल–पुथल के बीच भारत के साथ सम्बंधों पर श्री अधिकारी ने कहा कि इस मामले में भारतीय मीडिया ने भी गलत खबरों को तवज्जों दी। जिसके कारण नेपाल के संविधान और मधेशी आंदोलन को लेकर भारत का रूख स्पष्ट नहीं हो सका। ये भारतीय मीडिया का ही असर था कि नेपाल में आन्दोलनों को सिर्फ मधेशी आन्दोलन और भारत के रूझान के रूप में दिखाया गया। वहीं, भारतीय राजनेताओं ने भी सिर्फ राजनीतिक संबंधों के आधार पर बातों का क्रम चलाया, जिसमें स्थानीय जनता का कोई सम्पर्क नहीं रहा। इसी का लाभ उठाते हुए नेपाल सरकार ने जनता को यह समझाया कि भारत की विशेष रूचि सिर्फ मधेशियों के हित को लेकर हैं। नेपाल की सरकार ने अपनी जनता से कहा कि भारत ने नेपाल के संविधान का स्वागत नहीं किया। भारत कभी नहीं चाहता कि हमारा अपना संविधान हो। इसी कारण नेपाली जनता के मन में भारत के प्रति काफी रोष है। जबकि होना यह चाहिए था कि भारत सरकार सिर्फ राजनैतिक स्तर के बजाय व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं आम जनता से सीधे संवाद करती तो लोगों तक भारत का रूख स्पष्ट होता और भारत पूरे आन्दोलन को शान्त कराने की दिशा में मध्यस्थता कराने का काम करता।

दीपक अधिकारी ने भारत–नेपाल संबंधों पर रोशनी डालते हुए बताया कि नेपाल के अंदर हो रही राजनीतिक हलचल से भारत भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा क्योंकि नेपाल की सीमा पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों ओर से भारत से लगी हुई है। भारत का नेपाल के साथ आत्मीय लगाव शुरू से रहा है। भारत और नेपाल की संस्कृति एक जैसी है। भारत के प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से दोनों देशो के बीच काफी मधुरता आयी थी। भूकंप के समय भारत की तत्परता ने नेपाली जनता को काफी प्रभावित किया था जिसे भारतीय मीडिया ने अपने टीआरपी के चक्कर मे धूमिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मधेशी आंदोलन के आर्थिक नाकेबंदी के चलते वहाँ की जनता का बुराहाल है। सरकार एक तरफ से मधेश को नेपाल का अंग ही मानने से इनकार कर रही है। मधेश के लोगों को नजरअदांज करने के कारण मधेशियों के लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है। आन्दोलनकारियों की मांग है कि मधेश के लोग भी नेपाली हैं और सभी को समान अधिकार मिलना ही चाहिए।

नेपाल की समस्या के समाधान के लिए सुझाव के तौर पर दीपक अधिकारी कहते हैं कि नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों ने संविधान बनाने की दिशा में एकपक्षीय निर्णय लिया, जिसका विरोध हुआ और नेपाल में भयावह स्थिति बनी। यह नेपाल के राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह पता करें की कौन सी माँग उनके नागरिकों के हित से जुड़ी है और कौन सी नहीं। घरेलू समस्याओं का ठीक तरीके से समाधान नहीं कर पाना राजनीतिज्ञों की कूटनीतिक विफलता और अदूरदर्शिता को दर्शाता है। उनका कहना है कि नेपाल एक छोटा सा परिवार है और यहीं पर निवास करने वाले हिमल, पहड़ और तराई एक ही माँ के बेटे हैं। घर के किसी सदस्य को तकलीफ होती है तो परिवार के सभी लोग पीड़ा से कराह उठते हैं, यही वर्तमान स्थिति नेपाल की भी है। समाधान के लिए पहल करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को तराई जाकर नागरिकों से सीधे संवाद करना चाहिए ताकि सरल और सहज समाधान निकल सके। ■

अधिवेशन समापन

बौद्धिक सैनिक की तरह कार्य करते हैं परिषद के कार्यकर्ता

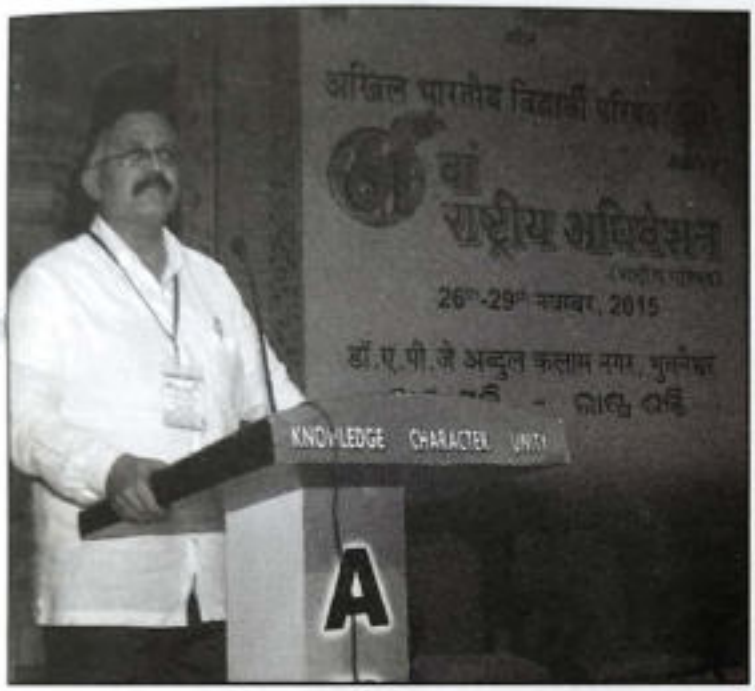

भुवनेश्वर में हुए 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समारोप सत्र में परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन ने सभी कार्यकर्ताओं को उद्‌बोधन देते हुए कहा कि अभाविप एक सामाजिक सेवा का संगठन है। जिसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता 'बौद्धिक सैनिक' (Intellectual Soldier) के तौर पर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सामान्यतः विद्यार्थी परिषद एक विशिष्ट छात्र संगठन है, देश व समाज के लिए सदैव चिन्तक के तौर पर विचार करता है। विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन 21 वर्षों के बाद भुवनेश्वर में हो रहा है। इस अधिवेशन का जो स्वरूप, विचार और विद्यार्थी परिषद को जिस ढ़ंग से दिशा मिली है वह जगन्नाथ की कृपा से है। मुझे लगता है कि जो जगन्नाथ जी का नया रुप आया है, उसी तरह विद्यार्थी परिषद के काम के लिए कार्यकर्ताओं को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यहाँ विद्यार्थी परिषद का नवकलेवर हुआ है। यहाँ के जगन्नाथ मंदिर ने सबको इतना समाज से जोड़ा हुआ है कि यहाँ जातपात का कोई स्थान नहीं है। यहाँ सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं।

भुवनेश्वर के शिक्षा–ओ–अनुसंधान विश्वविद्यालय में आयोजित अधिवेशन के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए श्री रघुनंदन ने कहा कि यहाँ आकर शैक्षणिक परिवार की कल्पना भी साकार हुई है। जिस प्रकार कार्यक्रम के उद्‌घाटन अवसर पर कई प्रोफेसर स्वागत टीम में शामिल रहे और छात्रों–युवाओं को एक शैक्षणिक संस्थान में एक बेहतर माहौल के बीच समाज और देश को जोड़ने वाले विचारों को सुनने का मौका मिला यह अपने आप में अद्‌भुत है।

परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ने बताया कि इस अधिवेशन में हमने एक नया आयाम शुरू किया जो 'साविष्कार' है। जिसकी वेबसाइट भी शुरू की गयी है। साथ ही भारत से बाहर विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी तीन कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया। वहीं हमने कृषि एवं मेडिकल के क्षेत्र में भी छात्रों के बीच कार्य करना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा परिषद अगले वर्ष मई माह से समाज दर्शन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। जिसका लक्ष्य समाज को देखना और सर्वेक्षण के कार्यों को पूरा करना होगा।

कार्यकर्ताओं को परिषद की मजबूती बताते हुए श्री रघुनन्दन ने कहा कि परिषद के विचारों का ही कमाल है कि अभाविप ने जिस भी क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया वहां के छात्र स्वयं ही आकर हमसे जुड़ते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता साहसी और कर्मठ है, जो स्वामी विवेकानन्द के विचारों को समाज के बीच ले जा रहा है। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि परिषद की सक्रियता यूंही बनी रहे और लगातार परिषद का विस्तार होता रहे। ■

देश में काम करने को प्रतिबद्ध युवा

ठुकराये विदेशी कम्पनियों के करोड़ों के पैकेज

नई दिल्ली। टीवी पर एक विज्ञापन आता है, जिसमें एक युवक कहता है कि अब समय है देश के लिए कुछ करने का। यहाँ तक कि फिल्म 'सत्याग्रह' में भी इस पक्ष को रखा गया है। लेकिन अब यह केवल विज्ञापन और फिल्मों तक ही सीमित नही है, बल्कि आम जिंदगी में भी दिखने लगा है। भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (IIT) के कुछ छात्रों ने विदेशों से मिली नौकरी के अवसरों को ठुकराकर देश में काम करने का मन बनाया है। कैंपस प्लेसमेंट सेशन में छात्रों ने करीब दो करोड़ रुपये तक के सालाना ऑफर को भी ठुकरा दिया। कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान का प्रभाव बता रहे हैं। यदि यही आलम रहा तो 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सेशन में ऐसे छात्रों की संख्या काफी बढ़ जायेगी।

आईआईटी दिल्ली में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के प्रमुख प्रोफेसर शशि माथुर ने बताया कि इस बार के प्लेसमेंट सत्र में बेहद दिलचस्प बात ये देखने को मिल रही है कि विद्यार्थी विदेश में अच्छे सैलरी पैकेज से ज्यादा महत्व देश में नौकरी को दे रहे हैं। इसी सोच का नतीजा है कि अभी प्लेसमेंट सत्र को पांच ही दिन गुजरे हैं और ऐसे कई छात्र सामने आएं हैं, जिन्होंने एक लाख डॉलर सहित अन्य खर्चों के साथ ऑफर किए गए करीब एक से दो करोड़ रुपये तक के ऑफर ठुकरा दिए। प्रो. माथुर ने बताया कि इस बार विद्यार्थी विदेशी के स्थान पर देशी कंपनियों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कंपनियों के स्तर पर देखें तो इस बार सबसे ज्यादा ऑफर आइटी कंपनियां दे रही हैं। इसके बाद कंसल्टिंग और कोर (तकनीकी) कंपनियां जॉब ऑफर कर रही हैं। तीसरा नंबर फाइनेंस सेक्टर का है, जबकि अंतिम पायदान पर एनालिटिक्स है।

कैंपस प्लेसमेंट के शुरुआत दौर में कुछ जापानी कंपनिया भी विद्यार्थियों की भर्ती करने के लिए कैंपस में आई हैं। बताया जा रहा है कि इस बार बीते साल के मुकाबले बीस से तीस लाख रुपये सालाना पैकेज के ऑफर की संख्या में इजाफा हुआ है। कई छात्र ऐसे भी हैं, जिन्हें चार से ज्यादा जॉब ऑफर हो रहे हैं। प्रो. शशि माथुर ने कहा कि इस बार प्लेसमेंट के लिए 10 फीसद ज्यादा कंपनी आई हैं। लिहाजा उम्मीद है कि सैलेरी पैकेज और ज्यादा बढ़ेंगे। जहां तक जॉब सेक्टर की बात है तो अभी तक सबसे ज्यादा 43 फीसद जॉब ऑफर आइटी इंडस्ट्री से मिला है, जबकि सबसे कम चार फीसद ऑफ एनालिटिक्स के क्षेत्र से। ■

सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय में अभाविप की तीन पदों पर जीत

वाराणसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए छात्र संघ चुनाव के लिहाज से वर्ष 2015 काफी सुखद रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, इलाहाबाद समेत कई विश्वविद्यालयों में जीत हासिल करने के बाद वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में भी अभाविप प्रत्याशियों की जीत हुई। सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय में अभाविप ने चार में से तीन पदों पर अपना परचम लहराया।

कड़ी सुरक्षा व भारी गहमागहमी के बीच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में अभाविप ने उपाध्यक्ष, महामन्त्री और पुस्तकालय मन्त्री पद अपने झोली में डाला जबकि एनएसयूआई के खाते में मात्र एक सीट आयी। अभाविप के शिवशंकर प्रसाद यादव 'मंगल' उपाध्यक्ष पद पर, महामंत्री पद पर जीतेंद्र कुमार व पुस्तकालय मंत्री पद पर सूर्य प्रकाश उपाध्याय निर्वाचित घोषित किए गए।

इस बार विश्वविद्यालय में रिकार्ड 72.16 फीसद छात्रों ने मतदान किया। कुल 1886 मतदाताओं में से 1361 ने मताधिकार का प्रयोग किया। विभिन्न पदों पर 75 मत अवैध निकले।

चुनाव अधिकारी प्रो. हेतराम कछवाह के अनुसार, उपाध्यक्ष पद पर अभाविप के शिवशंकर ने 511 मत पाकर एनएसयूआई के शुभम शर्मा को 149 मतों से हराया। जबकि महामंत्री पद पर भी विद्यार्थी परिषद प्रत्याशी जीतेंद्र कुमार ने 727 मत पाकर एनएसयूआई उम्मीदवार राजेश चौबे को 210 मतों से पराजित किया। इसी प्रकार पुस्तकालय मंत्री पद पर अभाविप प्रत्याशी सूर्य प्रकाश उपाध्याय ने एनएसयूआई प्रत्याशी दीपक कुमार सैनी को 212 मतों से पराजित किया। सूर्य प्रकाश 778 व दीपक को 566 मत मिले। परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद कुलपति प्रो. यदुनाथ दुबे ने नव–निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई।

विश्वविद्यालय के संकायों में भी अभाविप समर्थित प्रतिनिधियों का दबदबा रहा। वेद वेदांग संकाय प्रतिनिधि पद पर दीपक कुमार पांडेय (190) व धीरेंद्र कुमार (156) मत हासिल कर निर्वाचित घोषित हुए। इसके अलावा साहित्य संस्कृति संकाय के लिए अतुल कुमार व सुशील दुबे, दर्शन संकाय हेतु जिज्ञासु कुमार दुबे, श्रमण विद्या संकाय के लिए ब्रह्माजी द्विवेदी व विपिन तिवारी एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय से निशा प्रजापति का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। ■

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
राष्ट्रीय पदाधिकारी : 2015–16

अध्यक्ष	:	डा. नागेश ठाकुर	शिमला
महामंत्री	:	श्री विनय बिदरे	बंगलुरु
उपाध्यक्ष	:	डा. श्रीनिवास बल्ली	बागलकोट, कर्नाटक
		डा. सुश्री पुष्कर बाला	टाटानगर, झारखण्ड
		डा. एस. सुबय्या	चेन्नई, तमिलनाडू
		डा. धर्मेन्द्र कुमार साही	देहरादून, उत्तरांचल
		डा. प्रशान्त राऊत	भुवनेश्वर, ओडिशा
मंत्री	:	श्री श्रीहरि बोरिकर	गुवाहाटी, असम
		श्री आशीष चौहान	मुम्बई, महाराष्ट्र
		श्री निखिल रंजन	पटना, बिहार
		श्री. पी. सुरेश	विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश
		श्री किशोर बर्मन	कोलकाता, प.बंगाल
		श्री संजय कुशराम	अनूपपुर, महाकोशल
		सुश्री मोनिका चौधरी	दिल्ली
		श्री आलोक पांडेय	काशी
संगठन मंत्री	:	श्री सुनील आम्बेकर	मुम्बई
सह संगठन मंत्री	:	श्री के. एन. रघुनंदन	भोपाल
		श्री जी. लक्ष्मण	हैदराबाद
		श्री श्रीनिवास	दिल्ली
कोषाध्यक्ष	:	श्री श्याम अग्रवाल	जयपुर
सह कोषाध्यक्ष	:	श्री गितेश सामंत	ठाणे, महाराष्ट्र
सचिवालय सचिव	:	श्री चेतस सुखड़िया	मुम्बई
कार्यालय मंत्री	:	श्री राहुल शर्मा	मुम्बई

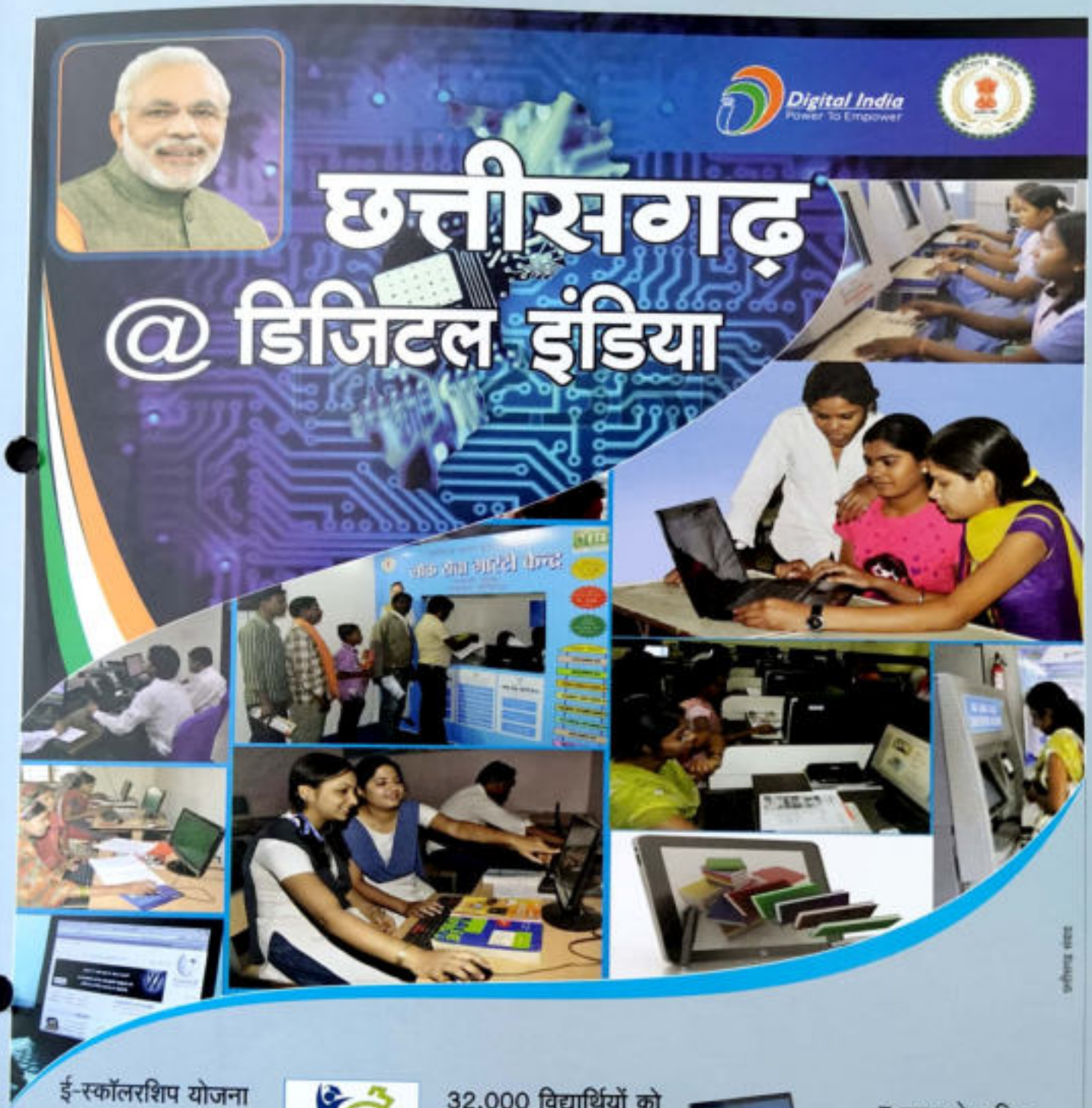

ई-स्कॉलरशिप योजना के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाईन छात्रवृत्ति सुविधा

Scholarship

32,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप और 71 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट का निःशुल्क वितरण

7 लाख से अधिक नागरिकों को रंगीन मतदाता परिचय पत्र

100 महाविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी

162 लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से 65 हजार से अधिक ट्रांजेक्शन

ग्रामीण चॉइस परियोजना के माध्यम से 8 लाख बैंक खाते खुले

11 लाख नागरिकों का आधार पंजीयन

330 चॉइस केन्द्रों के माध्यम से 22 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन

RNI No. 32464/78

100 लगाओ, पुलिस बुलाओ

मदद तुरन्त

**किसी भी
आपदा या विपत्ति में
पुलिस सहायता के लिए
करें डायल 100**

- प्रदेश भर में कम्प्यूटर, जीपीएस, वायरलेस, पी.ए. सिस्टम आदि से लैस 1000 वाहन तैनात।
- 24 घण्टे सेवा उपलब्ध।
- आधुनिकतम तकनीक से लैस कंट्रोल रूम।

**100
लगाओ
पुलिस
बुलाओ**

प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हो,
यह हमारी जिम्मेदारी है।
मध्यप्रदेश के 60वें स्थापना दिवस के
अवसर पर प्रारंभ हो रही
डायल-100 सेवा
नागरिकों की सुरक्षा में
एक उपयोगी कदम साबित होगी।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

1 नवंबर, 2015

**से सेवा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर,
जबलपुर, उज्जैन, सागर और रीवा में प्रारंभ
शेष सभी जिलों में भी शीघ्र ही सेवा शुरू होगी.**

देश भक्ति - जनसेवा — मध्यप्रदेश पुलिस